Kamal.Sandesh kamalsandesh.org KamalSandesh

कमल संदेश

वर्ष-20, अंक-06 16-31 मार्च, 2025 (पाक्षिक) ₹20

'प्रधानमंत्री मोदीजी नारी सशक्तीकरण के ध्येय के साथ देश को आगे बढ़ा रहे हैं'

'भारत अब महिला-नीत विकास के मार्ग पर चल रहा है'

बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) में 06 मार्च, 2025 को 'अभिनंदन समारोह' में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा का स्वागत करते हिमाचल प्रदेश भाजपा के नेतागण

बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) में 06 मार्च, 2025 को भाजपा जिला कार्यालय 'दीपकमल' की आधारशिला रखते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा

कटरा (जम्मू एवं कश्मीर) में 01 मार्च, 2025 को विधायक प्रशिक्षण वर्ग में भाग लेते भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा

पटना (बिहार) में 25 फरवरी, 2025 को भाजपा कोर कमेटी एवं मंत्रिपरिषद् की बैठक के दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा

26 फरवरी, 2025 को तमिलनाडु के कोयंबटूर, तिरुवन्नामलाई एवं रामनाथपुरम जिला भाजपा कार्यालयों का उद्घाटन करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

हैदराबाद (तेलंगाना) में 28 फरवरी, 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस समारोह को संबोधित करते रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 महिलाओं का आशीर्वाद मेरी शक्ति, पूंजी और सुरक्षा कवच है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर गुजरात में दो योजनाओं जी-सफल (आजीविका बढ़ाने के लिए अंत्योदय परिवारों के लिए गुजरात योजना) और जी-मैत्री (ग्रामीण आय में परिवर्तन के लिए...

09 'प्रधानमंत्री मोदीजी नारी सशक्तीकरण के ध्येय के साथ देश को आगे बढ़ा रहे हैं'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 8 मार्च...

10 भाजपा कार्यालय ऑफिस नहीं, बल्कि संस्कार केन्द्र होता है : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने...

13 'भारत एवं यूरोप के बीच साझा मूल्यों पर आधारित एक मजबूत साझेदारी है'

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष सुश्री उर्सुला वॉन डेर लेयेन 27-28 फरवरी 2025 को यूरोपीय संघ के कमिशनर के समूह का नेतृत्व करते हुए...

31 मध्य प्रदेश कृषि एवं खनिज के मामले में भारत के शीर्ष राज्यों में से एक है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 फरवरी को मध्य प्रदेश के भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स...

लेख

'विकसित भारत' के स्वप्न को साकार करते हमारे डिजिटल प्रयास / **अश्विनी वैष्णव** 24
महिला विकास से महिला-नेतृत्व वाले विकास तक / **अन्नपूर्णा देवी** 26
शुचिता, सुशासन व समर्पण के संगम थे अटल बिहारी वाजपेयी / **तरुण चुघ** 27
नारी सशक्तीकरण हमारी प्राथमिकता / **भजनलाल शर्मा** 29

अन्य

हमारे लिए साल का हर दिन 'मातृ देवो भव' है: प्रधानमंत्री 08
दिल्ली में 'महिला समृद्धि योजना' को महिला दिवस पर मिली मंजूरी 09
'राजनीतिक पदों के मोह से ऊपर उठें' 11
अब तमिलनाडु में डीएमके की देशविरोधी सरकार को खत्म करने का समय आ गया है : अमित शाह 13
स्वस्थ धरा खेत हरा 14
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान 16
जन औषधि दिवस का उत्सव पूरे देश में 'जन औषधि: दाम कम, दवाई उत्तम' थीम के साथ मनाया गया 18
'ग्रामोत्थान के माध्यम से नानाजी देशमुख जी ने दीनदयाल जी के अंत्योदय के सिद्धांत को जमीन पर उतारने का काम किया' 19
हमने कृषि को विकास का पहला इंजन माना है: नरेन्द्र मोदी 21
'2014 से सरकार ने 3 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है' 22
एमएसएमई क्षेत्र भारत के विनिर्माण और औद्योगिक विकास का आधार है: प्रधानमंत्री 23
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 32

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए विष्णु मित्तल द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। संपादक- डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

'विकसित भारत' के लिए विकास के साथ-साथ विरासत को मजबूत करना भी जरूरी है, इसलिए हमें अर्बन नक्सलियों से सावधान रहना है।

(07 मार्च, 2025)

जगत प्रकाश नड्डा

जब हम कमल के निशान को लेकर चले थे, तब उस समय लोग हमसे कहते थे कि किस पार्टी के साथ चल रहे हो, ये सत्ता में कभी नहीं आएगी। तब हम कहते थे कि हम सत्ता में आने के लिए नहीं हैं, हम भारत की तस्वीर बदलने के लिए आए हैं। सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं है, सत्ता माध्यम है। सत्ता हमारी मंजिल नहीं है, सत्ता बस जनता की सेवा करने का रास्ता है। (06 मार्च, 2025)

अमित शाह

मोदी सरकार सहकार से शक्ति, सहयोग और समृद्धि के तीन सूत्रों के साथ-साथ profit for people के सूत्र को भी चरितार्थ कर रही है।

(03 मार्च, 2025)

राजनाथ सिंह

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा इस बात पर ध्यान दिया गया है कि संस्थाएं silos में कार्य न करें बल्कि 'whole of the government' अप्रोच से काम करें।

(04 मार्च, 2025)

बी.एल. संतोष

श्री बाबूलाल मरांडी को झारखंड, भाजपा विधायक दल के नेता एवं झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता चुने जाने पर बधाई। उनका लंबा अनुभव सत्तारूढ़ पार्टी पर अंकुश लगाने और झारखंड के कल्याण को सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

(07 मार्च, 2025)

नितिन गडकरी

गरीबों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा लागू की गई 'प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना' के तहत गरीबों को कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध हो रही हैं। इस योजना के तहत गरीबों को औसत बाजार मूल्य की तुलना में 50 से 90 प्रतिशत कम दरों पर दवाइयां मिलती हैं। सस्ती दवाओं के साथ-साथ जन औषधि परियोजना रोजगार भी उपलब्ध करा रही है। (07 मार्च, 2025)

संपादकीय

महिला विकास से महिला-नीत विकास की ओर

आज जब पूरा देश 8 मार्च, 2025 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रेरक एवं दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की महिलाओं के तेजी से बढ़ते कदम से 'विकसित भारत' का संकल्प और भी अधिक दृढ़ हुआ है। 'नारी शक्ति' के पूरे सामर्थ्य को देश सेवा में सन्नद्ध करने के प्रयासों को महिला विकास से महिला-नीत विकास (वीमेन लेड डेवलपमेंट) में परिवर्तित होते देखा जा सकता है। महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थितियों को सुधारने के लिए अनेक परिवर्तनकारी नीतियों एवं पहलों के माध्यम से हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी, उन्हें सशक्त एवं समर्थ करने वाली योजनाओं के द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। वित्तीय समावेशन तथा उद्यमशीलता कार्यक्रमों से लेकर न्यायिक सुधार एवं सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों से एक ऐसे वातावरण का निर्माण हुआ है, जिसमें एक महिला भारत के विकास में अग्रणी भूमिका निभा सके तथा इस प्रक्रिया में उनका सकारात्मक योगदान सुनिश्चित हो।

आज जब एक विकसित, आत्मनिर्भर एवं समावेशी भारत का लक्ष्य देश का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महिलाओं के जीवन में गरिमा एवं सुविधा को सरकार द्वारा प्राथमिकता दिए जाने पर बल दिया है। अनेक योजनाओं के अलावा, 'इज्जत घर' के रूप में शौचालयों का निर्माण, महिलाओं के जन-धन बैंक खाते, निःशुल्क गैस कनेक्शन, हर घर नल से जल, मातृत्व अवकाश का 12 से 26 सप्ताह तक बढ़ाए जाने जैसे कदमों से नारी शक्ति को अपार संभावनाओं से सशक्त कर देश के भविष्य के लिए उनके सकारात्मक योगदानों को सुनिश्चित किया गया है। साथ ही, महिला सुरक्षा के लिए कड़े कानून जिसमें बालिका के साथ बलात्कार के लिए 20 वर्ष कारावास तथा मृत्युदंड के प्रावधान, तीन तलाक पर कड़े कानून तथा धारा 35(ए) का निरस्तीकरण जिससे जम्मू एवं कश्मीर की महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हुई, जैसे कदमों से पूरे देश में महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण का निर्माण हुआ है। लोकसभा एवं राज्यों के विधानसभाओं में 33% महिला भागीदारी सुनिश्चित करते हुए सुरक्षा बलों में महिलाओं को स्थायी कमीशन, सुरक्षा बल के तीनों अंगों में महिला अग्निवीरों के लिए प्रावधान तथा सैनिक विद्यालयों एवं राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी में महिलाओं के प्रवेश सुनिश्चित होने से महिलाओं के लिए अब तक बंद अवसरों के नए द्वार खुल गए हैं। लखपति दीदी तथा नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाओं के साथ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, मिशन शक्ति, स्टैंड अप इंडिया जैसे अभियान मोदी सरकार की महिला-नीत विकास के सिद्धांत के लिए अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

आज जब एक विकसित, आत्मनिर्भर एवं समावेशी भारत का लक्ष्य देश का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महिलाओं के जीवन में गरिमा एवं सुविधा को सरकार द्वारा प्राथमिकता दिए जाने पर बल दिया है। अनेक योजनाओं के अलावा, 'इज्जत घर' के रूप में शौचालयों का निर्माण, महिलाओं के जन-धन बैंक खाते, निःशुल्क गैस कनेक्शन, हर घर नल से जल, मातृत्व अवकाश का 12 से 26 सप्ताह तक बढ़ाए जाने जैसे कदमों से नारी शक्ति को अपार संभावनाओं से सशक्त कर देश के भविष्य के लिए उनके सकारात्मक योगदानों को सुनिश्चित किया गया है

भारत ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में बड़ी छलांग लगाई है। मातृ मृत्यु दर में भारी गिरावट, 5 वर्ष से कम शिशु मृत्यु दर में भारी कमी एवं महिला की औसत आयु में भारी वृद्धि महिला स्वास्थ्य सेवा, उसकी उपलब्धता तथा गुणवत्ता में व्यापक सुधार को परिलक्षित करता है। केंद्रीय बजट 2025-26 में महिला संबंधी पहलों में 4.49 लाख करोड़ रुपए का रिकार्ड आवंटन जो पिछली दस वर्षों में लगभग तीन गुना अधिक आवंटन है, से महिलाओं के बढ़ते वित्तीय समावेशन, उद्यमशीलता एवं रोजगार-उपलब्धता संभव हुई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करिश्माई एवं सुदृढ़ नेतृत्व में विभिन्न राज्यों में भाजपा सरकारों ने महिला सशक्तीकरण एवं उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सुभद्रा योजना, महतारी वंदन योजना, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना एवं महिला समृद्धि योजना जैसी अनेक योजनाओं का शुभारंभ हुआ है। मोदी सरकार ने हर क्षेत्र में महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित किया है; फलतः आज विज्ञान, शिक्षा, अंतरिक्ष, खेलकूद, राजनीति, शासन-प्रशासन, स्वास्थ्य, उद्यमशीलता जैसे हर क्षेत्र में महिलाएं देश का नाम रोशन कर रही हैं। अब इसमें कोई संदेह नहीं कि महिला-नीत विकास से 'विकसित भारत' का पथ प्रशस्त हो रहा है। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस

महिलाओं का आशीर्वाद मेरी शक्ति, पूंजी और सुर

प्रधानमंत्री ने गुजरात में लखपति दीदियों से बातचीत की व विकास योजनाओं का शुभारंभ किया

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आठ मार्च को गुजरात के नवसारी जिले में विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया तथा लखपति दीदी कार्यक्रम में भाग लिया व लखपति दीदियों से बातचीत की। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने बड़ी संख्या में उपस्थित माताओं, बहनों और बेटियों के प्यार, स्नेह और आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त किया और देश की सभी महिलाओं को इस विशेष दिन की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में उन्हें 'मां गंगा' का आशीर्वाद मिला था, जबकि आज मातृशक्ति के महाकुंभ में उन्हें आशीर्वाद मिला

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर गुजरात में दो योजनाओं जी-सफल (आजीविका बढ़ाने के लिए अंत्योदय परिवारों के लिए गुजरात योजना) और जी-मैत्री (ग्रामीण आय में परिवर्तन के लिए व्यक्तियों की गुजरात मेंटरशिप और एक्सिलारेशन योजना) के शुभारंभ पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि विभिन्न योजनाओं के धन को सीधे महिलाओं के बैंक खातों में डाला गया है और इस उपलब्धि के लिए सभी को बधाई दी।

श्री मोदी ने कहा कि आज का दिन महिलाओं को समर्पित है और उन्होंने सभी का आभार व्यक्त किया तथा गर्व के साथ कहा कि वे स्वयं को दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति मानते हैं, पैसों के मामले में नहीं, बल्कि करोड़ों माताओं, बहनों और बेटियों के आशीर्वाद के कारण। उन्होंने जोर देकर कहा, "ये आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी ताकत, पूंजी और सुरक्षा कवच हैं।"

महिलाओं के सम्मान के महत्व पर जोर देते हुए, क्योंकि यह समाज और राष्ट्र के विकास की दिशा में पहला कदम है, प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डालते हुए कहा, "भारत अब तीव्र प्रगति के लिए महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के मार्ग पर चल रहा है।" श्री मोदी ने कहा कि सरकार महिलाओं के जीवन में सम्मान और सुविधा दोनों को प्राथमिकता देती है।

उन्होंने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालयों के निर्माण का उल्लेख किया, जिन्हें 'इज्जत घर' या 'सम्मान का घर' भी कहा जाता है, जिससे उनकी गरिमा बढ़ी है और करोड़ों महिलाओं के लिए बैंक खाते खोले

क्षा कवच है: नरेन्द्र मोदी

गए हैं, जिससे उन्हें बैंकिंग प्रणाली में एकीकृत किया गया है। श्री मोदी ने महिलाओं को धुएं के कारण होने वाली कठिनाइयों से बचाने के लिए उज्ज्वला सिलेंडर के प्रावधान पर भी प्रकाश डाला।

मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह

श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया है। उन्होंने मुस्लिम बहनों की ओर से तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाने की मांग को स्वीकार किया और कहा कि सरकार ने लाखों मुस्लिम बहनों के जीवन की रक्षा के लिए एक सख्त कानून बनाया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जब जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू था, तब महिलाओं को कई अधिकारों से वंचित रखा जाता था। अगर वे राज्य के बाहर किसी से शादी करती थीं, तो वे पैतृक संपत्ति पर अपना अधिकार खो देती थीं और अनुच्छेद 370 हटने के साथ ही जम्मू-कश्मीर में महिलाओं को अब अपने अधिकार मिल गए हैं।

समाज, सरकार और बड़े संस्थानों के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं के लिए बढ़ते अवसरों को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "महिलाएं हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं, चाहे वह राजनीति हो, खेल हो, न्यायपालिका हो या पुलिस हो।" उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। श्री मोदी ने उल्लेख किया कि केंद्र सरकार में सबसे अधिक महिला मंत्री हैं और संसद में महिलाओं की उपस्थिति भी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि 2019 में 78 महिला सांसद चुनी गईं और 18वीं लोकसभा में 74 महिला सांसद सदन का हिस्सा हैं।

न्यायपालिका में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी

न्यायपालिका में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को रेखांकित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जिला न्यायालयों में उनकी उपस्थिति 35 प्रतिशत से अधिक है। कई राज्यों में सिविल जजों के रूप में 50 प्रतिशत से अधिक नई भर्तियों में महिलाएं हैं। श्री मोदी ने प्रकाश डाला, "भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें लगभग आधे स्टार्टअप में नेतृत्व की भूमिका में महिलाएं हैं।"

उन्होंने प्रमुख अंतरिक्ष मिशनों का नेतृत्व करने वाली महिला वैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण योगदान का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट हैं। उन्होंने नवसारी में कार्यक्रम के आयोजन और सुरक्षा में महिलाओं की भूमिका को भी स्वीकार किया, जिसमें महिला पुलिस अधिकारियों और अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंधन किया।

प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के साथ अपनी पिछली बातचीत को साझा किया, जिसमें उन्होंने भारत की महिलाओं की ताकत के प्रमाण के रूप में उनके उत्साह और आत्मविश्वास को देखा। उन्होंने अपना विश्वास दोहराया कि 'विकसित भारत' का संकल्प पूरा होगा और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महिलाएं सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

गुजरात: महिला-नेतृत्व वाले विकास का एक बेहतरीन उदाहरण

गुजरात को महिला-नेतृत्व वाले विकास का एक बेहतरीन उदाहरण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसने देश को महिलाओं की कड़ी मेहनत और ताकत से विकसित एक सफल सहकारी मॉडल प्रदान किया है। उन्होंने अमूल की वैश्विक मान्यता को रेखांकित किया और बताया कि कैसे गुजरात के गांवों की लाखों महिलाओं ने दूध उत्पादन को एक क्रांति में बदल दिया है। श्री मोदी ने कहा कि गुजराती महिलाओं ने न केवल खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया है। उन्होंने गुजराती महिलाओं द्वारा शुरू किए गए लिज्जत पापड़ की सफलता पर भी रोशनी डाली, जो अब सैकड़ों करोड़ रुपये का ब्रांड बन गया है।

प्रधानमंत्री ने देशवासियों को भरोसा दिलाया कि वे उनके सपनों को पूरा करने में किसी भी बाधा को आने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह एक बेटा अपनी मां की सेवा करता है, उसी तरह वह भारत माता तथा भारत की माताओं और बेटियों की भी सेवा कर रहा है। उन्होंने अपने भाषण के अंत में दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि लोगों की कड़ी मेहनत, समर्पण और आशीर्वाद 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेंगे और उन्होंने एक बार फिर देश की हर मां, बहन और बेटी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। ■

प्रधानमंत्री ने लखपति दीदियों के साथ किया संवाद

हमारे लिए साल का हर दिन 'मातृ देवो भव' है: प्रधानमंत्री

महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आठ मार्च को गुजरात के नवसारी में लखपति दीदियों के साथ भावपूर्ण संवाद किया और महिला सशक्तीकरण के महत्व तथा समाज में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने कहा कि भले ही आज पूरी दुनिया महिला दिवस मना रही है, लेकिन हमारी तो परंपराओं और संस्कृति में ही इसकी शुरुआत मां के प्रति श्रद्धा, 'मातृ देवो भव' से होती है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए साल का हर दिन 'मातृ देवो भव' है।

लखपति दीदियों में से एक ने शिवानी महिला मंडल के साथ काम करने का अपना अनुभव साझा किया, जहां वे सौराष्ट्र के सांस्कृतिक शिल्प, मोतियों के काम से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने 400 से अधिक बहनों को मोतियों के काम का प्रशिक्षण दिया है, जबकि अन्य बहनें मार्केटिंग और अकाउंटिंग का काम संभालती हैं। प्रधानमंत्री ने पूछा कि क्या मार्केटिंग टीम राज्य के बाहर भी जाती है, जिस पर उन्होंने पुष्टि की कि उन्होंने भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों का दौरा किया है।

प्रतिभागी ने एक अन्य लखपति दीदी पारुल बहन की सफलता पर प्रकाश डाला, जो 40,000 रुपये से अधिक कमाती हैं। इस तरह से लखपति दीदियों की उपलब्धि को स्वीकार किया गया। श्री मोदी ने तीन करोड़ लखपति दीदियों को बनाने का अपना सपना व्यक्त किया और उन्होंने माना कि यह आंकड़ा पांच करोड़ तक पहुंच सकता है।

एक अन्य लखपति दीदी ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि वह कड़ी मेहनत करके कुछ ही वर्षों में करोड़पति बन जाएंगी। उन्होंने सफलता का मार्ग दिखाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। एक ड्रोन दीदी ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि वह लगभग 2 लाख रुपये कमा रही है। इसके बाद श्री मोदी ने एक बैंक सखी से बातचीत की, जो हर महीने करीब 4 से 5 लाख रुपए का कारोबार करती है। एक अन्य महिला ने अन्य महिलाओं को भी अपनी तरह लखपति दीदी बनाने की इच्छा जाहिर की।

भारतीय महिलाएं: एक महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति

प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन व्यापार मॉडल में प्रवेश करने के महत्व पर जोर दिया और उनकी पहल को उन्नत करने के लिए सरकारी सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि कई महिलाएं जमीनी स्तर पर कमाई कर रही हैं और दुनिया को पता होना चाहिए कि भारतीय महिलाएं सिर्फ घरेलू काम तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि एक महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति हैं।

श्री मोदी ने कहा कि ग्रामीण महिलाएं भारत की आर्थिक मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं तकनीक को जल्दी अपना लेती हैं और ड्रोन दीदियों के साथ अपना अनुभव साझा किया, जिन्होंने तीन से चार दिनों के भीतर ड्रोन चलाना सीखा और ईमानदारी से अभ्यास किया। उन्होंने संघर्ष करने, निर्माण करने, पालन-पोषण करने और धन अर्जित करने की भारत की महिलाओं की अंतर्निहित शक्ति पर प्रकाश डाला। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इस शक्ति से देश को बहुत लाभ होगा। ■

प्रधानमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सफल महिलाओं को सौंपे

महिला शक्ति और उपलब्धियों को प्रेरणादायी सम्मान देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आठ मार्च को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उन महिलाओं को सौंप दिए, जो विविध क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं।

सफल महिलाओं ने प्रधानमंत्री के एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया: "अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, परमाणु प्रौद्योगिकी और महिला सशक्तीकरण...

हम एलिना मिश्रा, एक परमाणु वैज्ञानिक और शिल्पी सोनी, एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं और हम #महिला दिवस पर प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का संचालन करने को लेकर रोमांचित हैं।

हमारा संदेश है कि भारत विज्ञान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है और इसलिए हम अधिकाधिक महिलाओं से इसमें आगे बढ़ने का आह्वान करते हैं।"

भाजपा महिला मोर्चा : 'महिला दिवस कार्यक्रम', नई दिल्ली

'प्रधानमंत्री मोदीजी नारी सशक्तीकरण के ध्येय के साथ देश को आगे बढ़ा रहे हैं'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 8 मार्च, 2025 को नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित 'महिला दिवस कार्यक्रम' को संबोधित किया और समग्र राष्ट्र एवं दिल्ली की महिलाओं को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की। श्री नड्डा ने कहा कि देश की महिलाओं की चिंता और सशक्तीकरण का कार्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केवल भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। कार्यक्रम के दौरान मंच पर दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती वानथी श्रीनिवासन, दिल्ली भाजपा प्रभारी श्री बैजयंत जय पांडा, सह प्रभारी श्रीमती अलका गुर्जर, दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा एवं सांसद श्रीमती कमलजीत सहरावत सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे।

महिला-नीत विकास पर जोर

श्री नड्डा ने कहा कि वे महिला दिवस पर नारी शक्ति को नमन करते हैं और दिल्ली की महिलाओं को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने भाजपा सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली की यह जीत महिलाओं के आशीर्वाद और सहयोग से संभव हुई है। जब 1952 में भारतीय जनसंघ बना, उस समय से ही नारी शक्ति को आगे लाने पर जोर दिया गया। उस समय श्रीमती विजया राजे सिंधिया को उपाध्यक्ष बनाकर महिला सशक्तीकरण के कार्यों से जोड़ा गया था और तब से यह यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। आज भाजपा सरकार का फोकस वीमेन लेड डेवलपमेंट पर है और प्रधानमंत्री मोदीजी नारी सशक्तीकरण के ध्येय साथ देश को आगे बढ़ा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत या विकसित भारत की कल्पना तब तक संभव नहीं है जब तक नारी के मन में आत्मविश्वास उत्पन्न नहीं होता और जब आत्मविश्वास जागृत होता है, तब हम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ते हैं।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम

श्री नड्डा ने कहा कि महिला आरक्षण का जो कार्य यूपीए और अन्य विपक्षी दल तीन दशकों में नहीं कर पाए, उसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मात्र तीन दिनों में कर दिखाया। लोकसभा और राज्यसभा में सबसे अधिक महिलाएं भाजपा से हैं और आने वाले समय में यह कानून सुनिश्चित करेगा कि लोकसभा में 33 प्रतिशत महिलाएं सदस्य बनें।

महिला समृद्धि योजना

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महिला समृद्धि योजना लाने की घोषणा की थी और हमने अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सहायता देंगे। आज खुशी की बात है कि इस योजना को हकीकत में बदलने के लिए दिल्ली की भाजपा सरकार ने 5000 रुपए करोड़ का बजट आवंटित किया है। ■

दिल्ली में 'महिला समृद्धि योजना' को महिला दिवस पर मिली मंजूरी

दिल्ली सरकार ने 2,500 मासिक सहायता देने हेतु एक साल के लिए 5,100 करोड़ रुपये मंजूर किए

दिल्ली की महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने आठ मार्च को महिलाओं को 2,500 रुपये का मासिक मानदेय प्रदान करने के लिए 'महिला समृद्धि योजना' को मंजूरी दी।

मीडिया को संबोधित करते हुए श्रीमती रेखा गुप्ता ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर कहा कि कैबिनेट ने 'महिला समृद्धि योजना' को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा, "हमने एक कैबिनेट बैठक की और योजना को मंजूरी दे दी है, जो हमने चुनाव के समय महिलाओं को 2,500 रुपये प्रदान करने का वादा किया था। हमने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए दिल्ली के बजट में 5,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।"

श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सरकार ने समिति का गठन किया है, एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा और योजना के लिए पंजीकरण जल्द ही शुरू होगा। ■

भाजपा कार्यालय ऑफिस नहीं, बल्कि संस्कार केन्द्र होता है : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 6 मार्च, 2025 को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में आयोजित जिला कार्यालय 'दीपकमल' शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के विकास, संगठन के विस्तार और कार्यालयों की स्थापना पर जोर दिया। श्री नड्डा ने कहा कि कांग्रेस अब परिवार-केंद्रित पार्टी बन गई है, जबकि भाजपा एक वैचारिक पार्टी है। 2019 में धारा 370 हटाकर भाजपा ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी के संकल्प को पूरा किया और जम्मू-कश्मीर को पूरी तरह भारत में समाहित किया। कार्यक्रम के दौरान मंच पर हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, हिमाचल प्रदेश नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश प्रभारी श्री श्रीकांत शर्मा, हिमाचल प्रदेश सह-प्रभारी श्री संजय टंडन, राज्यसभा सांसद श्री सिकंदर कुमार सहित अन्य नेतागण उपस्थित रहे।

भाजपा कार्यालय हेतु मोदीजी का आग्रह

श्री नड्डा ने कहा कि आज उन्हें भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का भी शिलान्यास और भूमिपूजन करने का सौभाग्य मिला। 1994 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हिमाचल के प्रभारी बने और जब वह पहली बार शिमला आए, तो उन्होंने पार्टी कार्यालय के विषय में पूछा लेकिन उस समय पार्टी का कोई कार्यालय नहीं था। तब उन्होंने कहा कि यह तस्वीर बदलनी होगी और उनके प्रभारी रहते हुए प्रदेश का कार्यालय होना चाहिए। श्री नरेन्द्र मोदी ने उस समय गुजरात फोन करके तीन जीप और 4-5 कंप्यूटर दिलाते हुए कहा था कि जल्दी से जमीन ढूंढ कर कार्यालय बनाया जाए। भाजपा बैसाखियों पर नहीं चलती, बल्कि अपने पांव पर खड़ी होती है। वर्ष 1994 में श्री नरेन्द्र मोदी प्रभारी बने, 1995 में भाजपा कार्यालय के लिए जमीन खरीदी गई और 1998 में हिमाचल भाजपा कार्यालय की स्थापना हुई। पार्टी के प्रति प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का लगाव इस बात से झलकता है। आज भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी हो गई कि अब हम कहते हैं कि उस कार्यालय को शिमला का कार्यालय बनाया जाएगा और पार्टी कार्यालय को अलग बनाएंगे। आने वाले समय में एक भव्य कार्यालय शिमला में भी बनकर तैयार किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जब आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि हर प्रदेश में एक बड़ा भाजपा कार्यालय बनना चाहिए और हर जिले में भी एक कार्यालय होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित किया देशभर में 772 कार्यालय बनाए जाएंगे और 579 कार्यालय बनकर तैयार हो चुके हैं। आज इसी कड़ी में बिलासपुर में भी कार्यालय का शिलान्यास किया जा चुका है। इसे कार्यालय कहा जा रहा है, क्योंकि ऑफिस 10 बजे खुलता है और 5 बजे बंद हो जाता है, लेकिन कार्यालय शाम के 5 बजे के बाद ही चहकता है। कार्यकर्ता उसके बाद ही अपने दैनिक जीवन से फुरसत पाकर राजनैतिक कार्य में जुड़ता है और उसे आगे बढ़ाता है। इसलिए कार्यालय के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। कार्यालय कोई बैठने की जगह नहीं है, बल्कि यह संस्कार केन्द्र है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की इच्छा है कि कार्यालय सबसे मॉडर्न होना चाहिए, उसमें वॉर रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल, वाई-फ़ाई और कंप्यूटर सेक्शन होना चाहिए। कार्यालय में रेफरेंस सेक्शन, रिसर्च सेंटर होना चाहिए ताकि बिलासपुर का कोई व्यक्ति जब कार्यालय आए, तो एक बटन में बिलासपुर का इतिहास जान सके। राजनैतिक कार्यकर्ता को हर विषय की जानकारी होनी चाहिए।

भाजपा का संगठन सबसे सशक्त

श्री नड्डा ने कहा कि 1989 में पालमपुर अधिवेशन हुआ था। उस समय शांता कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। उस अधिवेशन में हमने राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने का संकल्प पारित किया था। आज भाजपा का संगठन सबसे सशक्त है। मैं जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, उसके 973 कमेटियां गठित हैं, जो कि देश के कुल जिलों से भी अधिक हैं। इसके अलावा, हमारे 15 हजार 432 ब्लॉकों में संगठनात्मक कार्य चल रहा है। हमारे पास 1 लाख 60 हजार शक्ति केंद्र हैं और 6 लाख 80 हजार बूथों पर बूथ कमेटियां सक्रिय हैं। यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक और संगठित राजनीतिक पार्टी है।

श्री नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की 13 राज्यों में स्वनिर्मित सरकार है, जबकि 19 राज्यों में एनडीए सरकार है। लोकसभा में 240 सांसद, राज्यसभा में 98 सांसद और हमारे 1,664 विधायक हैं। इसके अलावा, हमारे 162 एमएलसी सदस्य और 100 से अधिक निर्वाचित मेयर हैं। भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक, कैडर-बेस और संगठित पार्टी है। यह न केवल अपने विचारों के आधार पर कार्य कर रही है, बल्कि जनता का प्रेम, सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त कर पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ रही है। ■

'राजनीतिक पदों के मोह से ऊपर उठें'

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी विधायकों से अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देने तथा लोगों के साथ आत्मीय संबंध बनाए रखने का आह्वान किया। श्री नड्डा 1 मार्च, 2025 को कटरा, जम्मू-कश्मीर में आयोजित दो दिवसीय विधायक प्रशिक्षण वर्ग के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे।

अगस्त, 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किये जाने के बाद आयोजित प्रथम बजट सत्र से पूर्व, विधानसभा की कार्यवाही में पार्टी विधायकों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कटरा में भाजपा ने यह 'विधायक प्रशिक्षण वर्ग' आयोजित किया था।

विधायकों को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने 'कार्यकर्ता निर्माण' पर जोर दिया और विधायकों से राजनीतिक पदों के मोह से ऊपर उठने का आग्रह किया।

एक विधायक एवं विपक्ष के नेता के रूप में अपने अनुभव को साझा करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि पद अस्थायी होते हैं, लेकिन लोगों का विश्वास स्थायी होता है।

उन्होंने विधायकों को 'कृषि विज्ञान केन्द्रों', 'आशा कार्यकर्ताओं की बैठकों' और सरकारी स्कूलों में 'अभिभावक-शिक्षक संवाद' जैसे मंचों के माध्यम से समुदायों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने की सलाह दी।

उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि विधायकों को जनता की शिकायतों का प्रभावी समाधान करने के लिए अच्छे श्रोता बनने की आवश्यकता है तथा समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच नियमित रूप से प्रवास करना चाहिए।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में भाजपा मुख्य विपक्षी दल की भूमिका

निभा रही हैं। यह पहली बार है कि हम इतने बड़े जनादेश के साथ आए हैं और हमारा मत-प्रतिशत सत्तारूढ़ पार्टी एनसी से भी बेहतर है।

उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक विधानसभा के अंदर एवं बाहर जम्मू-कश्मीर में 'डबल इंजन' वाली सरकार न होने के नुकसान को भी जनता के समक्ष रखें।

इस वर्ग में अपने विचार रखते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि राष्ट्रवादी विचारधारा को ध्यान में रखकर आगामी बजट सत्र में जनकल्याण से जुड़े मुद्दों को उठाया जाएगा और हमारे विधायक भी पूरी तैयारी के साथ अपनी बात रखें।

श्री नड्डा ने भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं जम्मू-कश्मीर के प्रभारी श्री तरुण चुग, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह एवं जम्मू-कश्मीर भाजपा अध्यक्ष श्री सत शर्मा के साथ कटरा में दो दिवसीय वर्ग का प्रवास करने से पहले त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में भी पूजा-अर्चना की। ■

तीन नए प्रदेश भाजपाध्यक्ष निर्वाचित

सत शर्मा

मदन राठौर

दिलीप जायसवाल

हाल ही में भारतीय जनता पार्टी—जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान एवं बिहार प्रदेश अध्यक्षों के निर्वाचन संपन्न हुए। 24 जनवरी, 2025 को श्री सत शर्मा भाजपा, जम्मू एवं कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 22 फरवरी, 2025 को श्री मदन राठौर भाजपा, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। 04 मार्च, 2025 को श्री दिलीप जायसवाल भाजपा, बिहार प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ■

तेलंगाना में भाजपा ने 3 में से 2 एमएलसी सीटें जीतीं

भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना में विधान परिषद् (एमएलसी) चुनाव में तीन में से दो सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया, जिससे राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा। मेडक-करीमनगर-आदिलाबाद-निजामाबाद (शिक्षक) निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के श्री मलका कोमारैया विजयी हुए। वहीं, श्री चिन्नामेल अंजी रेड्डी ने करीमनगर-निजामाबाद-आदिलाबाद-मेडक (स्नातक) निर्वाचन क्षेत्र से विजय प्राप्त की। तेलंगाना में 27 फरवरी को एमएलसी चुनाव हुए थे और 3 मार्च को वोटों की गिनती हुई थी। ■

तमिलनाडु में नवनिर्मित जिला भाजपा कार्यालयों का उद्घाटन

अब तमिलनाडु में डीएमके की देशविरोधी सरकार को खत्म करने का समय आ गया है : अमित शाह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह ने 26 फरवरी, 2025 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर, थिरुवन्नामलाई और रामनाथपुरम में नवनिर्मित जिला भाजपा कार्यालयों का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान तमिलनाडु भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री के. अन्नामलाई, केन्द्रीय मंत्री श्री एल मुरुगन, तमिलनाडु भाजपा प्रभारी श्री अरविंद मेनन, प्रदेश सह प्रभारी श्री सुधाकर रेड्डी, तमिलनाडु प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष श्री नैनार नागेन्द्रन सहित अन्य वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे।

श्री शाह ने कहा कि आज कोयम्बटूर के साथ थिरुवन्नमलाई और रामनाथपुरम के जिला कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय अन्य कार्यालयों से अलग है, अन्य राजनीतिक दलों के लिए कार्यालय एक ढांचा होता है, लेकिन भाजपा के लिए कार्यालय एक मंदिर होता है, जहां से पार्टी का संचालन होता है। ये तीनों कार्यालय आने वाले समय में जनसंपर्क और जन आंदोलन के केन्द्र बनेंगे।

> **हर भाजपा कार्यकर्ता नए उत्साह के साथ 2026 में एनडीए सरकार बनाने के लिए कमर कस रहा है**

श्री शाह ने तमिलनाडु के भाजपा कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि अब तमिलनाडु में डीएमके की देशविरोधी सरकार को खत्म करने का समय आ गया है। हर भाजपा कार्यकर्ता नए उत्साह के साथ 2026 में एनडीए सरकार बनाने के लिए कमर कस रहा है।

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद तमिल भाषा, तमिल संस्कृति और तमिलनाडु के सम्मान के लिए यदि किसी ने सबसे अधिक कार्य किया है, तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया है। पवित्र सेंगोल को संसद भवन में स्थापित करके भारत के लोकतंत्र के मंदिर में तमिल संस्कृति को प्राधान्य देने का काम प्रधानमंत्रीजी ने किया है। आज पूरे देश में सबसे खराब कानून व्यवस्था तमिलनाडु की है, प्रीमियम संस्थाओं और यूनिवर्सिटी में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, 700 दिनों के बाद वेंगाइवयाल घटना के दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। तमिलनाडु में अवैध शराब की शिकायत करने पर अवैध शराब बनाने वालों पर कार्रवाई करने की बजाय उसका विरोध करने वाले छात्रों की हत्या कर दी जाती है। राज्य में देशविरोधी प्रवत्ति भी चरम सीमा पर है, तमिलनाडु सरकार ने 1998 के बम धमाके के मास्टर माइंड की अंतिम यात्रा को सुरक्षा देने का कार्य किया है। ड्रग माफियाओं को ड्रग्स बेचने की खुली छूट मिली है, अवैध खनन करने वाले खनन माफिया राजनीति को भ्रष्ट करने में लगे हैं और भ्रष्टाचार में तो डीएमके के सभी नेताओं ने मास्टर डिग्री की हुई है। एक नेता कैश फॉर जॉब में फंसे हुए हैं, दूसरे नेता मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध लाल रेत के खनन में फंसे हुए हैं, तीसरे नेता आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे हैं, चौथे नेता कोयला घोटाले में फंसे हुए हैं, पांचवे नेता 6 हजार करोड़ की CRIDP योजना में आरोपित हैं और 2G घोटाला अभी खत्म ही नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि समाज के भ्रष्टाचारियों को चुन-चुन कर डीएमके ने मेंबरशिप ड्राइव में शामिल किया है।

उन्होंने कहा कि मोदीजी ने आपके सभी हितों की रक्षा करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि परिसीमन में दक्षिण के राज्यों की एक भी सीट प्रो-राटा के आधार पर कम न हो और सीटों की बढ़ोतरी में दक्षिण भारत के राज्यों को उचित हिस्सा मिले। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हमेशा मोदी सरकार पर तमिलनाडु के साथ अन्याय करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन सत्य यह है कि यूपीए की सरकार ने 2004 से 2014 के बीच ग्रांट एड एवं डेवोल्यूशन के रूप में तमिलनाडु को मात्र 1 लाख 52 हजार 901 करोड़ रुपए दिए, जबकि मोदी सरकार ने 2014 से 2024 के बीच तमिलनाडु को 5 लाख 8 हजार 337 करोड़ रुपए की ग्रांट एड और डेवोल्यूशन फंड दिया है। इसके अलावा 1 लाख 34 हजार करोड़ रुपए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अलग से दिए गए हैं। इसके बावजूद स्टालिन, मोदी सरकार पर अन्याय का आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा मोदी सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का मदुरई एम्स बनाया है, 6400 करोड़ रुपए मत्स्य पालन के लिए दिए हैं, आपदा प्रबंधन, पेट्रोलियम और गैस संबंधी 9000 करोड़ रुपए और कई स्मार्ट सिटी के लिए फंड दिया है।

श्री शाह ने सभी कार्यकर्ताओं से तमिलनाडु में डीएमके सरकार के भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिलाओं की असुरक्षा और देशविरोधी गतिविधियों का पर्दाफाश करने और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा तमिलनाडु की जनता के विकास, तमिल गौरव, भाषा और संस्कृति के लिए किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाने की अपील की। ■

'भारत एवं यूरोप के बीच साझा मूल्यों पर आधारित एक मजबूत साझेदारी है'

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष सुश्री उर्सुला वॉन डेर लेयेन 27-28 फरवरी 2025 को यूरोपीय संघ के कमिशनर के समूह का नेतृत्व करते हुए अपनी ऐतिहासिक आधिकारिक यात्रा की। यह अपने नए कार्यकाल की शुरुआत के बाद से यूरोपीय महाद्वीप के बाहर कमिश्नर के समूह की पहली यात्रा और भारत-यूरोपीय संघ द्विपक्षीय संबंधों के इतिहास में भी इस तरह की पहली यात्रा थी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष सुश्री उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने पुष्टि करते हुए कहा कि यूरोपीय संघ-भारत रणनीतिक साझेदारी ने उनके लोगों और व्यापक वैश्विक हित के लिए जोरदार लाभ प्रदान किए हैं। उन्होंने 20 वर्षों की भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी और 30 वर्षों से अधिक के भारत-ईसी सहयोग समझौते के आधार पर इस साझेदारी को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता जताई।

नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि लोकतंत्र, कानून का शासन और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुरूप नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था सहित साझा मूल्य और सिद्धांत भारत और यूरोपीय संघ को समान विचारधारा वाले और भरोसेमंद साझेदार बनाते हैं। वैश्विक मुद्दों का संयुक्त रूप से समाधान करने, स्थायित्व को बढ़ावा देने और आपसी समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की अब पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है।

नेताओं ने निम्न प्रमुख प्रतिबद्धता व्यक्त की

वर्ष के अंत तक एफटीए के समापन में तेजी

अपने-अपने वार्ता दलों को संतुलित, महत्वाकांक्षी और पारस्परिक रूप से लाभकारी एफटीए के लिए वार्ता को आगे बढ़ाने का काम सौंपें, जिसका उद्देश्य वर्ष के दौरान उन्हें पूरा करना है, जिसमें भारत-यूरोपीय संघ के बढ़ते व्यापार और आर्थिक संबंधों की केंद्रीयता और महत्व को पहचाना जाता है।

आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती

भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद् को आर्थिक सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, बाजार पहुंच और व्यापार में बाधाओं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने, भरोसेमंद और टिकाऊ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग, 6 जी, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, हरित और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए संयुक्त अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्रों में परिणाम-उन्मुख सहयोग को आकार देने के लिए अपनी भागीदारी को और सशक्त करने का निर्देश दें, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए बैटरी की रिसाइक्लिंग, समुद्री प्लास्टिक कूड़े और कचरे से हरित/नवीकरणीय हाइड्रोजन बनाने सहित इन क्षेत्रों में विश्वसनीय भागीदारी और उद्योग संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया जाए।

कनेक्टिविटी, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु

कनेक्टिविटी, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु, जल, स्मार्ट और टिकाऊ शहरीकरण और आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी के तहत सहयोग को और विस्तारित और गहरा करना और साथ ही स्वच्छ हाइड्रोजन, अपतटीय पवन, सौर ऊर्जा, टिकाऊ शहरी आवागमन, विमानन और रेलवे जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोग को तेज करने के लिए काम करना।

सहयोग के नए विशिष्ट क्षेत्रों को विकसित करना

यूरोपीय संघ के कमिश्नर और भारतीय मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय चर्चाओं के दौरान पहचाने गए सहयोग के नए विशिष्ट क्षेत्रों को विकसित करना, जिन्हें आपसी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए भविष्य के संयुक्त रणनीतिक एजेंडे में प्रतिबिंबित किया जाएगा।

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा

नई दिल्ली में जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान घोषित भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) को साकार करने के लिए ठोस कदम उठाना, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए), आपदा रोधी इन्फ्रास्ट्रक्चर गठबंधन (सीडीआरआई), उद्योग परिवर्तन के लिए नेतृत्व समूह (लीडआईटी 2.0) और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की संरचना में अपने सहयोग को मजबूत करना।

उच्च शिक्षा, अनुसंधान, पर्यटन

उच्च शिक्षा, अनुसंधान, पर्यटन, संस्कृति, खेल और युवाओं के बीच लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करना तथा ऐसे आदान-प्रदान को बढ़ाने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना। साथ ही, भारत की बढ़ती मानव पूंजी और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल और श्रम बाजार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कुशल कार्यबल और पेशेवरों के क्षेत्रों में कानूनी, सुरक्षित और व्यवस्थित प्रवास को बढ़ावा देना। ■

मृदा स्वास्थ्य कार्ड के एक दशक

स्वस्थ धरा खेत हरा

फरवरी, 2025 तक 17 राज्यों में 665 ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 19 फरवरी, 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में की थी। यह योजना देश के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने में राज्य सरकारों की सहायता के लिए शुरू की गई थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उनकी मिट्टी की पोषक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है, साथ ही मिट्टी के स्वास्थ्य और उसकी उर्वरता में सुधार के लिए पोषक तत्वों की उचित खुराक की सिफारिश भी करता है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल (www.soilhealth.dac.gov.in) देश भर में सभी प्रमुख भाषाओं और 5 बोलियों में एक समान और मानकीकृत प्रारूप में किसानों के लाभ के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार करने की सुविधा प्रदान करता है।

> मृदा स्वास्थ्य कार्ड में 12 मापदंडों के संबंध में मिट्टी की स्थिति शामिल होती है, अर्थात् नाइट्रोजन, फ़ॉस्फोरस, पोटैशियम, सल्फर (मैक्रो-पोषक तत्व); जिंक, लौह तत्व, तांबा, मैंगनीज, बोरन (सूक्ष्म पोषक तत्व); और पीएच (अम्लता या क्षारीयता), ईसी (विद्युत चालकता) और ओसी (कार्बनिक कार्बन)

मृदा स्वास्थ्य कार्ड में 12 मापदंडों के संबंध में मिट्टी की स्थिति शामिल होती है, अर्थात् नाइट्रोजन, फ़ॉस्फोरस, पोटैशियम, सल्फर (मैक्रो-पोषक तत्व); जिंक, लौह तत्व, तांबा, मैंगनीज, बोरन (सूक्ष्म पोषक तत्व); और पीएच (अम्लता या क्षारीयता), ईसी (विद्युत चालकता) और ओसी (कार्बनिक कार्बन)।

इसके आधार पर कार्ड खेत के लिए आवश्यक उर्वरक अनुशंसाओं और मिट्टी संशोधन को भी बताएगा। मिट्टी के नमूने आम तौर पर साल में दो बार लिए जाते हैं, क्रमशः रबी और खरीफ फसल की कटाई के बाद या जब खेत में कोई खड़ी फसल न हो।

ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं (वीएलएसटीएल) के लिए दिशा-

निर्देश जून, 2023 में जारी किए गए थे। वीएलएसटीएल की स्थापना व्यक्तिगत उद्यमियों यानी ग्रामीण युवाओं और समुदाय आधारित उद्यमियों द्वारा की जा सकती है, जिसमें स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), स्कूल, कृषि विश्वविद्यालय आदि शामिल हैं। लाभार्थी/ग्राम स्तरीय उद्यमी एक युवा होना चाहिए, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम और 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को भी वीएलएसटीएल के रूप में नामांकित किया जा सकता है।

फरवरी, 2025 तक 17 राज्यों में 665 ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं।

स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीएसईएंडएल), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) और राज्य सरकारों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों के 20 स्कूलों (10 केन्द्रीय विद्यालय और 10 नवोदय विद्यालय) में स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम पर एक पायलट परियोजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य छात्रों को टिकाऊ कृषि प्रथाओं के लिए मृदा स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना है। इन स्कूलों में 20 मृदा स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित की गईं।

कक्षा VI से XII तक के छात्रों और शिक्षकों के लिए मॉड्यूल विकसित और प्रसारित किए गए। कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली छात्रों द्वारा मिट्टी के नमूने एकत्र किए गए और छात्रों द्वारा मिट्टी का परीक्षण भी किया गया और एसएचसी तैयार किए गए। छात्रों ने उर्वरक और फसल की सिफारिश के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिश के बारे में भी किसानों को शिक्षित किया।

2024 तक 1020 स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहे हैं, 1000 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं और 125,972 छात्र नामांकित हैं।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को वर्ष 2022-23 से 'मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता' नाम से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) में एक घटक के रूप में विलय कर दिया गया है।

प्रौद्योगिकी प्रगति
एसएचसी मोबाइल ऐप

मृदा स्वास्थ्य कार्ड तक पहुंच को और आसान बनाने के लिए भारत सरकार ने 2023 में नई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में तकनीकी हस्तक्षेप किया। मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल को नया रूप दिया गया और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के साथ एकीकृत किया गया, ताकि सभी परीक्षण परिणामों को कैप्चर किया जा सके और मानचित्र पर देखा जा सके। योजना के कार्यान्वयन/निगरानी को सुचारू बनाने और किसानों को उनके मृदा स्वास्थ्य कार्ड तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन को अतिरिक्त सुविधाओं के साथ लैस किया गया है जैसेः

- मिट्टी के नमूने एकत्र करने वाले ग्राम स्तरीय उद्यमी/संचालक के लिए नमूना संग्रह क्षेत्र को सीमित करना
- स्थान के अक्षांश और देशांतर का स्वतः चयन
- बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के भू-मानचित्रित प्रयोगशालाओं से सीधे पोर्टल पर सभी नमूनों के नमूने और परीक्षण परिणामों को जोड़ने के लिए क्यूआर कोड तैयार करना

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ने पिछले एक दशक में भारत में कृषि पद्धतियों को बदल दिया है। 2015 से इसने किसानों को मिट्टी की पोषक स्थिति और इष्टतम उर्वरक उपयोग पर महत्वपूर्ण जानकारी देकर सशक्त बनाया है, जिससे टिकाऊ खेती को बढ़ावा मिला है और फसल उत्पादकता में सुधार हुआ है। स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसी पहलों ने छात्रों और स्थानीय समुदायों के बीच मृदा स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाई है

यह एप्लीकेशन पूरे भारत की ग्राफिक जानकारी प्रदान करता है और साथ ही कई स्तरों पर राज्य सीमा, जिला सीमा, तालुका सीमा, पंचायत सीमा और भूकर सीमा भी दिखाता है।

नई प्रणाली अप्रैल, 2023 में शुरू की गई थी और अब मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से नमूने एकत्र किए जा रहे हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड अब इस नए पोर्टल पर बनाए जाते हैं।

मृदा स्वास्थ्य कार्डों के डिजिटलीकरण के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा वेब आधारित कार्य प्रवाह अनुप्रयोग मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल डिजाइन और विकसित किया गया है।

निष्कर्ष

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ने पिछले एक दशक में भारत में कृषि पद्धतियों को बदल दिया है। 2015 से इसने किसानों को मिट्टी की पोषक स्थिति और इष्टतम उर्वरक उपयोग पर महत्वपूर्ण जानकारी देकर सशक्त बनाया है, जिससे टिकाऊ खेती को बढ़ावा मिला है और फसल उत्पादकता में सुधार हुआ है। स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसी पहलों ने छात्रों और स्थानीय समुदायों के बीच मृदा स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाई है।

एक मजबूत मोबाइल ऐप के साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया ने पहुंच, दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाया है। जैसे-जैसे यह योजना विकसित होती है, यह टिकाऊ कृषि विकास को बढ़ावा देने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भारत की मिट्टी के स्वास्थ्य की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहती है। ■

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान

2023-24 के लिए 9.2% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 2021-22 को छोड़कर पिछले 12 वर्षों में सबसे अधिक है

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 28 फरवरी को एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का दूसरा अग्रिम अनुमान (एसएई); वित्त वर्ष 2024-25 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही (क्यू3) के लिए जीडीपी के तिमाही अनुमान, इसके व्यय घटकों के साथ और जीडीपी, राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण के संशोधित अनुमान जारी किए। ये अनुमान राष्ट्रीय लेखा के जारी कैलेंडर के अनुसार स्थिर (2011-12) और वर्तमान दोनों मूल्यों पर जारी किए गए हैं।

वार्षिक अनुमान और वृद्धि दर

वास्तविक जीडीपी या स्थिर मूल्यों पर जीडीपी वित्तीय वर्ष 2024-25 में 187.95 लाख करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी का पहला संशोधित अनुमान 176.51 लाख करोड़ रुपये है। 2024-25 के दौरान वास्तविक जीडीपी में वृद्धि दर 6.5% अनुमानित है, जबकि 2023-24 में यह 9.2% थी। नॉमिनल जीडीपी या वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी वर्ष 2024-25 में 331.03 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंचने का अनुमान है, जबकि 2023-24 में यह 301.23 लाख करोड़ रुपये थी, जो 9.9% की वृद्धि दर दर्शाता है।

वर्ष 2024-25 में वास्तविक जीवीए 171.80 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है, जबकि वर्ष 2023-24 के लिए एफआरई 161.51 लाख करोड़ रुपये है, जो 2023-24 में 8.6% की वृद्धि दर की तुलना में 6.4% की वृद्धि दर दर्शाता है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान नॉमिनल जीवीए 300.15 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंचने का अनुमान है, जबकि 2023-24 में यह 274.13 लाख करोड़ रुपये है, जो 9.5% की वृद्धि दर दर्शाता है।

तिमाही अनुमान और वृद्धि दर

वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में वास्तविक जीडीपी या स्थिर मूल्यों पर जीडीपी 47.17 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में यह 44.44 लाख करोड़ रुपये थी, जो 6.2% की वृद्धि दर दर्शाती है। वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में नॉमिनल जीडीपी या वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी 84.74 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में यह 77.10 लाख करोड़ रुपये थी, जो 9.9% की वृद्धि दर दर्शाती है।

वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में वास्तविक जीवीए 43.13 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में यह 40.60 लाख करोड़ रुपये था, जो 6.2% की वृद्धि दर दर्शाता है। वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में नॉमिनल जीवीए 77.06 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में यह 69.90 लाख करोड़ रुपये था, जो 10.2% की वृद्धि दर दर्शाता है।

मुख्य बातें

- वित्त वर्ष 2024-25 में वास्तविक जीडीपी में 6.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में नॉमिनल जीडीपी की वृद्धि दर 9.9% रहने की उम्मीद है। दोनों विकास दरें उनके संबंधित प्रथम अग्रिम अनुमानों से ऊपर की ओर संशोधित की गई हैं।
- पहले संशोधित अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में वास्तविक जीडीपी में 9.2% की वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 2021-22 (कोविड के बाद का वर्ष) को छोड़कर पिछले 12 वर्षों में सबसे अधिक है। इस वृद्धि में 'विनिर्माण' क्षेत्र (12.3%), 'निर्माण' क्षेत्र (10.4%) और 'वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवा' क्षेत्र (10.3%) में दोहरे अंकों की वृद्धि दर का योगदान है।
- अंतिम अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 7.6% की वृद्धि दर देखी गई है, जिसमें मुख्य रूप से 'व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं' क्षेत्र (12.3%), 'वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं' क्षेत्र (10.8%) और 'बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएं' क्षेत्र (10.8%) में दोहरे अंकों की वृद्धि दर का योगदान है।
- वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में वास्तविक जीडीपी में 6.2% की वृद्धि का अनुमान है। वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही के लिए नॉमिनल जीडीपी में वृद्धि दर 9.9% अनुमानित की गई है।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को संशोधित कर 5.6% कर दिया गया है।
- वर्ष 2024-25 के दौरान 'निर्माण' क्षेत्र में 8.6% की वृद्धि दर रहने का अनुमान है, इसके बाद 'वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं' क्षेत्र (7.2%) और 'व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं' क्षेत्र (6.4%) का स्थान है।
- निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) में 2024-25 के दौरान 7.6% की अच्छी वृद्धि दर्ज होने की उम्मीद है, जबकि 2023-24 के दौरान 5.6% की वृद्धि दर्ज की गई थी। ■

उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे परियोजना-पर्वतमाला परियोजना के विकास को मिली मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने पांच मार्च को सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किमी रोपवे परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी। परियोजना को डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और स्थानांतरण (डीबीएफओटी) मोड पर 4,081.28 करोड़ रुपये की कुल पूंजी लागत पर विकसित किया जाएगा।

रोपवे को सार्वजनिक-निजी भागीदारी में विकसित करने की योजना है और यह सबसे उन्नत ट्राई-केबल डिटेचेबल गोंडोला (3एस) तकनीक पर आधारित होगा। इसकी डिजाइन क्षमता 1,800 यात्री प्रति घंटे प्रति दिशा (पीपीएचपीडी) होगी, जो प्रति दिन 18,000 यात्रियों को ले जाएगी।

रोपवे परियोजना केदारनाथ आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए वरदान होगी, क्योंकि यह पर्यावरण अनुकूल, आरामदायक और तेज़ कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और एक दिशा में यात्रा का समय लगभग 8 से 9 घंटे से घटाकर लगभग 36 मिनट कर देगी। केदारनाथ मंदिर तक की यात्रा गौरीकुंड से 16 किमी की चुनौतीपूर्ण चढ़ाई है और वर्तमान में इसे पैदल या टट्टू, पालकी और हेलीकॉप्टर द्वारा तय किया जाता है।

केदारनाथ 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में 3,583 मीटर (11,968 फीट) की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर साल में अक्षय तृतीया (अप्रैल-मई) से दीपावली (अक्टूबर-नवंबर) तक लगभग 6 से 7 महीने तीर्थयात्रियों के लिए खुला रहता है और इस मौसम के दौरान सालाना लगभग 20 लाख तीर्थयात्री यहां आते हैं। ■

कैबिनेट ने उत्तराखंड में गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब जी तक रोपवे परियोजना के विकास को दी मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने पांच मार्च को गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब जी तक 12.4 किलोमीटर रोपवे परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी। इस परियोजना को डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) मोड पर विकसित किया जाएगा, जिसकी कुल पूंजीगत लागत 2,730.13 करोड़ रुपये होगी।

वर्तमान में हेमकुंड साहिब जी की यात्रा गोविंदघाट से 21 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण चढ़ाई है और इसे पैदल या टट्टू या पालकी द्वारा पूरा किया जाता है। प्रस्तावित रोपवे की योजना हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों और फूलों की घाटी में आने वाले पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई है और यह गोविंदघाट और हेमकुंड साहिब जी के बीच हर मौसम में अंतिम मील की कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी।

हेमकुंड साहिब जी उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक अत्यंत श्रद्धेय तीर्थ स्थल है। इस पवित्र स्थल पर स्थापित गुरुद्वारा मई से सितम्बर के बीच साल में लगभग 5 महीने के लिए खुला रहता है और हर साल लगभग 1.5 से 2 लाख तीर्थयात्री यहां आते हैं। ■

पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी) में संशोधन को मिली मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पांच मार्च को पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी) में संशोधन को मंजूरी दे दी। इस योजना के तीन घटक हैं— राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी), पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण (एलएचएंडडीसी) और पशु औषधि। एलएचएंडडीसी के तीन उप-घटक हैं: गंभीर पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (सीएडीसीपी), मौजूदा पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण - मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई (ईएसवीएचडी-एमवीयू) और पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (एएससीएडी)।

एलएचडीसीपी योजना में पशु औषधि को एक नए घटक के रूप में जोड़ा गया है। दो वर्षों यानी 2024-25 और 2025-26 के लिए योजना का कुल परिव्यय 3,880 करोड़ रुपये है, जिसमें पशु औषधि घटक के तहत अच्छी गुणवत्ता वाली और सस्ती जेनेरिक पशु चिकित्सा दवा और दवाओं की बिक्री के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है।

पशुओं की उत्पादकता खुरपका और मुंहपका रोग (एफएमडी), ब्रुसेलोसिस, पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स (पीपीआर), सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड (सीएसएफ), लम्पी स्किन डिजीज आदि बीमारियों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। एलएचडीसीपी के कार्यान्वयन से टीकाकरण के माध्यम से बीमारियों की रोकथाम करके इन नुकसानों में कमी आएगी।

यह योजना मोबाइल पशु चिकित्सा लिंट्स (ईएसवीएचडी-एमवीयू) के उप-घटकों के माध्यम से पशुधन स्वास्थ्य देखभाल की डोर-स्टेप डिलीवरी और पीएम-किसान समृद्धि केंद्र और सहकारी समितियों के नेटवर्क के माध्यम से जेनेरिक पशु चिकित्सा दवा-पशु औषधि की उपलब्धता में सुधार का भी समर्थन करती है।

इस प्रकार यह योजना टीकाकरण, निगरानी और स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन के माध्यम से पशुधन रोगों की रोकथाम और नियंत्रण में मदद करेगी। इस योजना से उत्पादकता में सुधार होगा, रोजगार पैदा होगा, ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और बीमारी के बोझ के कारण किसानों को होने वाले आर्थिक नुकसान को रोका जा सकेगा। ■

जन औषधि दिवस का उत्सव पूरे देश में 'जन औषधि: दाम कम, दवाई उत्तम' थीम के साथ मनाया गया

एक सप्ताह तक चले उत्सव के 7वें दिन पीएमबीआई (फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया) ने सात मार्च को पूरे देश में 7वां जन औषधि दिवस 2025 मनाया, जिसमें 100 से अधिक प्रमुख कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में विभिन्न राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय तथा राज्य स्तर के मंत्रियों, सांसदों, विधानसभा सदस्यों, पार्षदों और अन्य जन प्रतिनिधियों सहित कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया, ताकि प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के लाभों पर विस्तार से चर्चा की जा सके और जनता को जागरूक और लाभान्वित किया जा सके।

यह कार्यक्रम 1 मार्च को पूरे देश में जन औषधि जन चेतना अभियान के साथ शुरू हुआ और 7 मार्च को जन औषधि दिवस 2025 के उत्सव के साथ समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम जन चेतना अभियान/पदयात्रा, हेरिटेज वॉक और स्वास्थ्य शिविर, जन औषधि बाल मित्र, एक कदम मातृ शक्ति की ओर, फार्मासिस्ट जागरूकता कार्यक्रम, आओ जन औषधि मित्र बनें; जन औषधि दिवस तक जारी रहे।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एम्स के जन औषधि केंद्र का दौरा किया और लाभार्थियों के साथ बातचीत की। केंद्र के मालिकों और जन औषधि योजना के लाभार्थियों ने भी अपने अनुभव साझा किए।

श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश साझा किया और देश के सभी नागरिकों को 7वें जन औषधि दिवस, 2025 की शुभकामनाएं दीं। सप्ताह भर चले उत्सव में इस महान परियोजना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पूरे देश में राष्ट्रीय पेंशनरों और जन औषधि तथा अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को 1.12 करोड़ से अधिक डिजिटल संदेश भेजे गए। MyGov पोर्टल के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करने के लिए 7 करोड़ से अधिक संदेश भी भेजे गए। ■

भारत सरकार का जनवरी, 2025 तक कुल व्यय 35,69,954 करोड़ रुपये रहा

केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 28 फरवरी को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार जनवरी, 2025 तक भारत सरकार का मासिक लेखा समेकित कर इसकी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है। इसकी मुख्य बातें निम्न हैं:

भारत सरकार को जनवरी, 2025 तक कुल प्राप्तियों में 24,00,412 करोड़ रुपये (वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान का 76.3%) प्राप्त हुए हैं, जिनमें 19,03,558 करोड़ कर राजस्व (केंद्र को शुद्ध कर), 4,67,630 करोड़ रुपये गैर-कर राजस्व और 29,224 करोड़ रुपये गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां शामिल हैं। इस अवधि तक भारत सरकार द्वारा कर हिस्से के हस्तांतरण के तौर पर राज्य सरकारों को 10,74,179 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2,53,929 करोड़ अधिक है।

इस दौरान भारत सरकार द्वारा कुल व्यय 35,69,954 करोड़ रुपये (वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान का 75.7%) रहा, जिनमें 28,12,595 करोड़ रुपये राजस्व खाते और 7,57,359 करोड़ रुपये पूंजी खाते में हुए। कुल राजस्व व्यय में से 8,75,461 करोड़ रुपए ब्याज भुगतान में तथा 3,37,733 करोड़ रुपए प्रमुख सब्सिडी में खर्च हुए। ■

रक्षा मंत्रालय ने सेना के टी-72 टैंकों के इंजन खरीद हेतु 248 मिलियन डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए

रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के टी-72 टैंकों के 1000 एचपी इंजन खरीद के लिए रूस के रोसोबोरोनएक्सपोर्ट के साथ 248 मिलियन डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। ये इंजन पूरी तरह से तैयार और असेंबल किए जाने के अर्ध-तैयार अवस्था में होंगे।

रक्षा मंत्रालय द्वारा सात मार्च को जारी एक बयान के अनुसार रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए इस सौदे में ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी के तहत इंजनों को जोड़ने और बाद में लाइसेंस प्राप्त उत्पादन के लिए रोसोबोरोनएक्सपोर्ट से चेन्नई के अवाडी स्थित आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (हैवी व्हीकल फैक्ट्री) को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी शामिल है।

टी-72 भारतीय सेना के बेड़े का मुख्य टैंक है, जो अभी 780 एचपी इंजन से युक्त है। टी-72 टैंकों के मौजूदा बेड़े को 1,000 एचपी इंजन से लैस करने से भारतीय सेना की युद्धक गतिशीलता और आक्रामक क्षमता बढ़ेगी। ■

केन्द्रीय गृह मंत्री ने चित्रकूट (मध्य प्रदेश) में नानाजी देशमुख की पुण्यतिथि पर संबोधित किया

'ग्रामोत्थान के माध्यम से नानाजी देशमुख जी ने दीनदयाल जी के अंत्योदय के सिद्धांत को जमीन पर उतारने का काम किया'

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 27 फरवरी को मध्य प्रदेश के चित्रकूट में 'भारत रत्न' नानाजी देशमुख की 15वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उप-मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ला सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा कि आज नानाजी देशमुख की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम के साथ दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा और भगवान राम के जीवन पर आधारित प्रस्तुति 'राम दर्शन' के लोकार्पण का भी कार्यक्रम रखा गया। उन्होंने कहा कि नानाजी देशमुख उन लोगों में शामिल हैं, जिनका जीवन कुछ वर्षों तक नहीं, बल्कि युगों तक अपना असर छोड़ता है और ऐसे लोग युग को परिवर्तनकारी बनाने का काम करते हैं।

श्री शाह ने कहा कि महाराष्ट्र में जन्म लेने वाले नानाजी बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे, संघ के प्रचारक बने, उत्तर प्रदेश को कार्य क्षेत्र बनाया, भारतीय जनसंघ के महामंत्री बने और दीनदयाल जी के साथ रहकर उत्तर प्रदेश में जनसंघ की नींव डालने के लिए हर खंड-प्रखंड तक प्रवास किया। नानाजी ने अपने जीवन का क्षण-क्षण और शरीर का कण-कण भारत माता को अर्पित कर शतायु होने का सौभाग्य प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि राजनीति में रहते हुए अजातशत्रु होकर दुनिया से जाना बड़ा कठिन है, लेकिन आज तक न तो सत्ता पक्ष और न ही विपक्ष के किसी नेता से नानाजी के बारे में कोई गलत बात सुनी।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि राजनीति में रहते हुए सर्व-स्वीकृति लाना बड़ा कठिन है, राजनीतिक उद्देश्यों से भी विरोध करना पड़ता है, लेकिन इतने लंबे जीवन में भी किसी ने नानाजी के विरोध का साहस नहीं किया और न ही उनका विरोध करना उचित समझा। उन्होंने कहा कि नानाजी ने कला, साहित्य, उद्योग, सेवा और राजनीति सहित लगभग हर क्षेत्र में संपर्क बनाया और उस क्षेत्र में स्वीकृति एवं सम्मान प्राप्त किया। एक जीवन में इतना सब कुछ प्राप्त करना काफी कठिन है।

नानाजी राजनीति में भी 'जल कमल' की तरह रहे

श्री अमित शाह ने कहा कि जब नानाजी की उम्र सिर्फ 60 साल थी, तब उन्होंने राजनीति से अलग होकर शेष जीवन 'एकात्म मानववाद' को जमीन पर उतारने का निर्णय किया। वह राजनीति में भी 'जल कमल' की तरह रहे, हर बुराई से खुद को अलग रखा और पूरा जीवन बुराइयों को दूर करने में व्यतीत किया। नानाजी ने अपनी कर्मठता से राजनीति में ऐसे सिद्धांत स्थापित किए हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि नानाजी के द्वारा किए गए छोटे-छोटे प्रयोगों ने भारत के गांवों का दृश्य-परिदृश्य बदलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि नानाजी ने ग्रामोत्थान के माध्यम से दीनदयाल जी के अंत्योदय के सिद्धांत

को जमीन पर उतारने का काम किया।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नानाजी देशमुख और दीनदयाल उपाध्याय के रूप में भारतीय जनसंघ ने एक ही कालखंड में दो महापुरुष देश की राजनीति को दिए। दोनों का जन्म 1916 में हुआ। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के बाद जब नीतियां बन रही थीं, तो लोग देश की नीतियों को चिंता के साथ देख रहे थे। देश की विदेश, अर्थ, कृषि और शिक्षा जैसी नीतियों में हमारे चिर पुरातन राष्ट्र की मिट्टी की सुगंध नहीं थी। उस समय की सरकार पश्चिम से लिए गए सिद्धांतों का हिन्दीकरण करके नीतियां बनाने का संतोष प्राप्त करती थी। उस वक्त पंडित दीनदयाल जी ने 'एकात्म मानववाद' का सिद्धांत प्रस्थापित करके बताया कि हमारा आर्थिक दर्शन, हमारी विदेश नीति कैसी हो और विश्व बंधुत्व के आधार पर विदेश को देखने का हमारा नजरिया कैसा हो। उन्होंने कहा कि यही सिद्धांत आज हमें विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनाने की ओर ले जा रहा है।

विरासत को सहेजकर विकास

श्री अमित शाह ने कहा कि पंडित दीनदयाल जी ने भारत के विकास के मॉडल को 'अंत्योदय' का नाम दिया यानी जब तक पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का विकास न हो जाए, तब तक उसके मायने नहीं रहते। उन्होंने कहा कि अंतिम व्यक्ति का विकास राष्ट्र के विकास का परिचायक होना चाहिए। श्री शाह ने कहा विरासत को सहेजकर विकास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नानाजी और दीनदयाल जी के अंत्योदय की राजनीति को आदर्श मानने वाले मोदी जी आज करोड़ों गरीबों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बीते 10 साल में 60 करोड़ गरीबों को घर, शौचालय, पेयजल, गैस सिलिंडर, 5 किलो अनाज, बिजली और पांच लाख रुपए तक के इलाज जैसी सुविधाएं दी गई हैं। उन्होंने कहा कि नानाजी ने ग्रामीण

भारत के विकास का जो प्रकल्प शुरू किया, जिसके अनुरूप आज गांव को गोकुल ग्राम बनाने की दिशा में काम हो रहा है।

श्री अमित शाह ने कहा कि नानाजी कुशल संगठक थे। उन्होंने कहा कि जब देश में आपातकाल लगा और लोकतंत्र और लोगों की स्वतंत्रता पर कुठाराघात हुआ, तब विपक्ष बिखरा हुआ था, मगर जन चेतना जागृत थी। उन्होंने कहा कि 19 महीनों के संघर्ष ने लोगों को तानाशाही के खिलाफ खड़ा कर दिया था। लोग लोकतंत्र को बचाना चाहते थे, चुनाव हुआ, उस समय की सरकार की घोर पराजय हुई और लोकतंत्र की विजय हुई। उन्होंने कहा कि नानाजी उन चुनिंदा नेताओं में थे जिन्होंने जनता पार्टी की रचना में बड़ी भूमिका अदा की। उन्होंने राष्ट्रप्रथम का सिद्धांत प्रस्थापित कर हमारी पार्टी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

पूरा जीवन संघ के संस्कारों से संस्कारित

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नानाजी के समग्र व्यक्तित्व को देखें तो पूरा जीवन संघ के संस्कारों से संस्कारित रहा। इसके साथ ही बाल गंगाधर तिलक के राष्ट्रवाद और महात्मा गांधी के 'ग्राम स्वराज' का अद्भुत मेल अगर किसी एक व्यक्ति में देखने को मिलता है तो वे नानाजी देशमुख हैं। इसलिए उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि एक पद्म विभूषण की भांति नानाजी ने क्रांतिमय जीवन जिया है और कई लोगों के जीवन में क्रांति लाने का काम किया है। इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने नानाजी को 'भारत रत्न' की उपाधि देने का भी काम किया। उन्होंने कहा कि नानाजी ऐसे लोगों में से हैं, जिन्हें उपाधि मिलने से वह उपाधि अलंकृत होती है।

श्री अमित शाह ने कहा कि नानाजी ने सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की, आज देशभर में हजारों की संख्या में यह विद्यालय बच्चों को शिक्षा और संस्कार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में सबसे पहला सरस्वती शिशु मंदिर नानाजी ने स्थापित किया था, जो आज वटवृक्ष बन चुका है। उन्होंने कहा कि नानाजी ने पूरा जीवन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को चरितार्थ करने के लिए काम किया।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय जनसंघ की स्थापना में दीनदयाल जी का बहुत योगदान रहा है। उन्होंने हमारे सारे सिद्धांतों और विचारों को आकार देने का काम किया। 'एकात्म मानववाद' का सृजन कर व्यक्ति से समष्टि तक की पूरी यात्रा को इसमें समाहित किया और राष्ट्र, समाज एवं व्यक्ति के विकास का पूर्ण दर्शन हम सबके लिए छोड़कर गए। श्री शाह ने कहा कि चित्रकूट धाम भारतवासियों के लिए श्रद्धा का केन्द्र है। प्रभु श्री राम ने सबसे ज्यादा समय अपने वनवास में यहीं बिताया।

मुख्य बातें

- नानाजी ने अपनी कर्मठता से राजनीति में ऐसे सिद्धांत स्थापित किए हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श बने रहेंगे
- नानाजी के प्रयासों ने देश के गांवों के सामाजिक व आर्थिक परिदृश्य को बदलने में अहम भूमिका निभाई
- दीनदयाल जी व नानाजी के अंत्योदय की राजनीति को आदर्श मानने वाले मोदी जी आज करोड़ों गरीबों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं
- संघ के संस्कार, तिलक महाराज का राष्ट्रवाद और गांधी जी का ग्राम स्वराज, इनका अद्भुत मेल नानाजी देशमुख जी के व्यक्तित्व में दिखता है
- नानाजी ने सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की, आज देशभर में हजारों की संख्या में यह विद्यालय बच्चों को शिक्षा और संस्कार दे रहे हैं ■

कमल पुष्प सेवा, समर्पण, त्याग, संघर्ष एवं बलिदान

विजय कुमार सिंह

श्री विजय कुमार सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के स्वयंसेवक सत्याग्रह (प्रथम और द्वितीय वर्ष) के लिए भूमिगत रहकर काम किया। उन्होंने 1975-1977 तक भारतीय जनसंघ में जिला मंत्री के दायित्व का निर्वहन किया और अक्टूबर 1975 से फरवरी 1977 तक आपातकाल के दौरान मीसा के तहत हिरासत में रहे। 1980 के बाद वे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद् के सदस्य बने। वे विश्व हिंदू परिषद् और भारतीय मजदूर संघ में राष्ट्रीय सचिव रहे। ■

श्री विजय कुमार सिंह

Date of Birth
23/03/1953

Gender
male

State
Bihar

District
Begusarai

Town/City
विचला टोला, वेगूसराय

Level
National

Post in Organisation
National Executive Member

Active years
1973-2021

बजट पश्चात् वेबिनार : कृषि एवं ग्रामीण समृद्धि

हमने कृषि को विकास का पहला इंजन माना है: नरेन्द्र मोदी

हम एक साथ दो बड़े लक्ष्यों पर काम कर रहे हैं— कृषि क्षेत्र का विकास और हमारे गांवों की समृद्धि

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि एवं ग्रामीण समृद्धि पर बजट पश्चात् वेबिनार को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा, "विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हमारे संकल्प बहुत स्पष्ट हैं और हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बना रहे हैं, जहां किसान समृद्ध और सशक्त हों।" उन्होंने कहा कि कृषि को विकास का पहला इंजन माना जाता है, जिससे किसानों को प्रतिष्ठित स्थान मिलता है। श्री मोदी ने कहा, "भारत एक साथ दो प्रमुख लक्ष्यों की ओर काम कर रहा है: कृषि क्षेत्र का विकास और गांवों की समृद्धि।"

श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि छह साल पहले लागू की गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को लगभग 3.75 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं और यह राशि सीधे 11 करोड़ किसानों के खातों में हस्तांतरित की गई है।

इस बात पर जोर देते हुए कि भारत का कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, प्रधानमंत्री ने कहा कि 10-11 साल पहले कृषि उत्पादन लगभग 265 मिलियन टन था, जो अब बढ़कर 330 मिलियन टन से अधिक हो गया है। इसी तरह, बागवानी उत्पादन 350 मिलियन टन से अधिक हो गया है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय बीज से बाजार तक सरकार के दृष्टिकोण, कृषि सुधारों, किसान सशक्तीकरण और एक मजबूत मूल्य श्रृंखला को दिया।

श्री मोदी ने देश की कृषि संभावना का पूरा उपयोग करने और इससे भी बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस दिशा में बजट में पीएम धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की गई है, जिसमें 100 सबसे कम उत्पादक कृषि जिलों के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि हाल के वर्षों में किए गए प्रयासों से देश में दालों का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन घरेलू खपत का 20 प्रतिशत हिस्सा अभी भी आयात पर निर्भर है, जिससे दालों के उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने चना और मूंग के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है, लेकिन अरहर, उड़द और मसूर के उत्पादन में तेजी लाने की जरूरत है।

फसलों की 2,900 से अधिक नई किस्में विकसित

श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि पिछले दशक में आईसीएआर ने अपने प्रजनन कार्यक्रम में आधुनिक उपकरणों और अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया है और इसके परिणामस्वरूप 2014 से 2024 के बीच अनाज, तिलहन, दलहन, चारा और गन्ना सहित फसलों की 2,900 से अधिक नई किस्में विकसित की गई हैं। उन्होंने बताया कि फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं और बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की गई है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के 2019 में शुभारंभ को याद करते हुए, जिसका उद्देश्य मूल्य श्रृंखला, बुनियादी ढांचे और मत्स्य पालन क्षेत्र के आधुनिकीकरण को मजबूत करना है, श्री मोदी ने कहा कि इस पहल ने मत्स्य पालन क्षेत्र में उत्पादन, मछली पकड़ने के बाद प्रसंस्करण और विपणन के कार्य में सुधार किया है, जबकि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र में निवेश बढ़ा है, जिसके परिणामस्वरूप मछली उत्पादन और निर्यात में दोगुनी वृद्धि हुई है।

3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को दोहराते हुए, जबकि प्रयासों के परिणामस्वरूप 1.25 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं, श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि ग्रामीण समृद्धि और विकास कार्यक्रमों के लिए इस बजट में की गई घोषणाओं से रोजगार के अनेक नए अवसर पैदा हुए हैं।

मुख्य बातें

- हमने बजट में 'पीएम धन धान्य कृषि योजना' की घोषणा की है, इसके तहत देश में सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा
- आज लोग पोषण के प्रति काफी जागरूक हो गए हैं, इसलिए बागवानी, डेयरी और मत्स्य उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए इन क्षेत्रों में काफी निवेश किया गया है; फलों और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं
- हमने बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की है
- हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है
- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत करोड़ों गरीबों को घर दिए जा रहे हैं, स्वामित्व योजना ने संपत्ति मालिकों को 'रिकॉर्ड ऑफ राइट्स' दिया है ■

बजट पश्चात् वेबिनार: रोजगार सृजन— जनमानस, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश

'2014 से सरकार ने 3 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है'

बजट में 10,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने का और अगले पांच वर्षों में चिकित्सा क्षेत्र में 75,000 सीटें जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पांच मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार पर बजट पश्चात् वेबिनार को संबोधित किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने वेबिनार के विषय वस्तु 'जनमानस, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश' के महत्व पर प्रकाश डाला, जो 'विकसित भारत' के लिए रोडमैप को परिभाषित करता है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि बुनियादी ढांचे, उद्योगों, लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश को समान रूप से प्राथमिकता दी गई है।

श्री मोदी ने कहा कि भारत की शिक्षा प्रणाली कई दशकों के बाद एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर रही है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आईआईटी का विस्तार, शिक्षा प्रणाली से प्रौद्योगिकी को जोड़ने और एआई की पूरी क्षमता का उपयोग जैसी प्रमुख पहलों पर जोर दिया।

इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि 2014 से सरकार ने 3 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है, प्रधानमंत्री ने 1,000 आईटीआई में सुधार और 5 उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना का उल्लेख किया। उन्होंने युवाओं को उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने वाले प्रशिक्षण से लैस करने के लक्ष्य पर जोर दिया।

चिकित्सा क्षेत्र का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस बजट में 10,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने का और अगले पांच वर्षों में चिकित्सा क्षेत्र में 75,000 सीटें जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में टेलीमेडिसिन सुविधाओं के विस्तार पर प्रकाश डाला।

1 लाख करोड़ रुपये के शहरी चुनौती कोष की स्थापना

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में अर्थव्यवस्था में निवेश भविष्य की दृष्टि से निर्देशित रहा है। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत की शहरी आबादी लगभग 90 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जिसके लिए योजनाबद्ध शहरीकरण की आवश्यकता है। उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपये के शहरी चुनौती कोष की स्थापना की पहल की घोषणा की, जिसमें शासन, बुनियादी ढांचे और वित्तीय स्थिरता पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा, साथ ही निजी निवेश को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने कहा, "भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है।" उन्होंने कहा कि इस बजट में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। उन्होंने शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के कॉर्पस फंड को मंजूरी दिए जाने का उल्लेख किया।

फरवरी, 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में आईएमएफ द्वारा की गई उल्लेखनीय टिप्पणियों का हवाला देते हुए श्री मोदी ने कहा कि 2015 से 2025 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था ने 66 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जिससे यह 3.8 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह वृद्धि कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से आगे निकल गई है और वह दिन दूर नहीं जब भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

मुख्य बातें

- हमने जनमानस, अर्थव्यवस्था और नवाचार को वही प्राथमिकता दी है जो हमने निवेश में बुनियादी ढांचे और उद्योगों को दी है
- लोगों में निवेश की कल्पना तीन स्तंभों पर टिकी है— शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य सेवा
- सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में टेलीमेडिसिन सुविधा का विस्तार किया जा रहा है
- डे-केयर कैंसर सेंटर और डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे के माध्यम से हम गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को अंतिम छोर तक ले जाना चाहते हैं
- देश भर में 50 पर्यटन स्थलों को पर्यटन पर केन्द्रित करके विकसित किया जाएगा
- सरकार ने इस बजट में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी दी गई है
- 'ज्ञान भारतम' मिशन के माध्यम से भारत की समृद्ध पांडुलिपि विरासत को संरक्षित करने की घोषणा बहुत महत्वपूर्ण है
- इस मिशन के माध्यम से एक करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित किया जाएगा ■

बजट पश्चात् वेबिनार : विनिर्माण और निर्यात

एमएसएमई क्षेत्र भारत के विनिर्माण और औद्योगिक विकास का आधार है: प्रधानमंत्री

केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर 40,000 से अधिक अनुपालन समाप्त किए गए, जिससे व्यापार करने में आसानी हुई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चार मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बजट पश्चात् वेबिनार को संबोधित किया। ये वेबिनार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को विकास का इंजन बनाने, विनिर्माण, निर्यात और परमाणु ऊर्जा मिशन, विनियामक, निवेश और व्यापार करने में आसानी जैसे विषयों पर आयोजित किए गए। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विनिर्माण और निर्यात पर बजट पश्चात वेबिनार बहुत महत्वपूर्ण हैं।

श्री मोदी ने कहा कि देश में एक दशक से भी अधिक समय से सरकारी नीतियों में निरंतरता देखने को मिली हैं और पिछले 10 वर्षों में देश ने सुधारों, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निरंतरता और सुधारों के आश्वासन ने उद्योग जगत में नया आत्मविश्वास आया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थिर नीति और बेहतर कारोबारी वातावरण किसी भी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कुछ वर्ष पहले सरकार ने 'जन विश्वास अधिनियम' पेश किया था और अनुपालन कम करने के प्रयास किए थे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर 40,000 से अधिक अनुपालन समाप्त किए गए, जिससे व्यापार करने में आसानी हुई। इस प्रकिया को जारी रखने पर जोर देते हुए उन्होंने उल्लेख किया कि सरकार ने आयकर के सरल प्रावधान पेश किए हैं और जन विश्वास 2.0 विधेयक पर काम जारी है।

श्री मोदी ने कहा, "वर्तमान में दुनिया राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है और पूरी दुनिया भारत को विकास केंद्र के रूप में देख रही है।" प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्तमान में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना से 14 क्षेत्र लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 750 से अधिक इकाइयों को मंजूरी दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश, 13 लाख करोड़ रुपये से अधिक का उत्पादन और 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात हुआ है।

6 करोड़ से अधिक एमएसएमई

श्री मोदी ने कहा, "एमएसएमई क्षेत्र भारत के विनिर्माण और औद्योगिक विकास का आधार है।" उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्ष 2020 में सरकार ने 14 वर्षों के बाद एमएसएमई की परिभाषा को संशोधित करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिससे एमएसएमई का यह भय समाप्त हो गया कि यदि वे अपने क्षेत्र का विस्तार करेंगे तो सरकारी लाभ खो देंगे। उन्होंने कहा कि देश में एमएसएमई की संख्या बढ़कर 6 करोड़ से अधिक हो गई है, जिससे करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं।

श्री मोदी ने कहा कि दस साल पहले एमएसएमई को लगभग 12

लाख करोड़ रुपये का ऋण मिला था, जो अब बढ़कर लगभग 30 लाख करोड़ रुपये हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट में एमएसएमई ऋणों के लिए गारंटी कवर को दोगुना करके 20 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 5 लाख रुपये की सीमा वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जाएंगे।

उन्होंने घोषणा की पहली बार उद्योग स्थापित करने वाली महिलाओं, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों के पांच लाख उद्यमियों को 2 करोड़ रुपए का ऋण मिलेगा।

मुख्य बातें

- पिछले 10 वर्षों में भारत ने सुधार, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और समावेशी विकास के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता दिखाई है
- 'सुधारों में निरंतरता और आश्वासन' ऐसा परिवर्तन है, जिससे हमारे उद्योग में नया आत्मविश्वास आया है
- आज दुनिया का हर देश भारत के साथ अपनी आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना चाहता है
- हमारे विनिर्माण क्षेत्र को इस साझेदारी का अधिकतम लाभ उठाने के लिए आगे आना चाहिए
- हमने 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया और सुधारों की गति को और तेज किया
- हमारे प्रयासों से अर्थव्यवस्था पर कोविड महामारी का प्रभाव कम हुआ, जिससे भारत को तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने में मदद मिली
- भारत की विनिर्माण यात्रा में शोध एवं विकास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसे आगे बढ़ाने और गति देने की आवश्यकता है
- शोध एवं विकास के माध्यम से हम नवोन्मेषी उत्पादों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, साथ ही उत्पादों में मूल्य संवर्धन भी कर सकते हैं ■

'विकसित भारत' के स्वप्न को साकार करते हमारे डिजिटल प्रयास

अश्विनी वैष्णव

महाराष्ट्र के बारामती में एक छोटा किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से कृषि के नियमों को पुनः परिभाषित कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप हम यहां कुछ असाधारण देख रहे हैं, जैसे उर्वरकों के उपयोग में कमी, पानी का कुशलता से उपयोग एवं अधिक पैदावार, ये सब एआई के बिना संभव नहीं था।

यह भारत की एआई-संचालित क्रांति की एक झलक मात्र है, जहां तकनीक और नवाचार अब प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि आम नागरिकों के जीवन को बदल रहे हैं। कई मायनों में इस किसान की कहानी एक बहुत बड़े परिवर्तन का सूक्ष्म रूप है, हमें जो 2047 तक 'विकसित भारत' के सपने के और करीब ले जाता है।

डिजिटल भविष्य

भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई), एआई, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पर विशेष ध्यान देते हुए अपने डिजिटल भविष्य को आकार दे रहा है। दशकों से भारत सॉफ्टवेयर में वैश्विक नेतृत्वकर्ता रहा है, लेकिन अब हम हार्डवेयर विनिर्माण में भी बड़ी प्रगति कर रहे हैं।

पांच सेमीकंडक्टर संयंत्र निर्माणाधीन हैं, जो वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में भारत की भूमिका को प्रमुखता से रखेंगे। आज, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद हमारे शीर्ष तीन निर्यातों में शुमार हैं और जल्द ही हम एक प्रमुख मील के पत्थर तक पहुंचगे - इस साल भारत की पहली मेक-इन-इंडिया चिप लॉन्च की जा सकती है।

एआई की शुरुआत एवं नवाचार

सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इसकी रीढ़ हैं, जबकि डीपीआई भारत की तकनीकी क्रांति को आगे बढ़ाने वाली प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करता है। भारत अपनी तरह के एक अनोखे एआई ढांचे के माध्यम से एआई को सर्वसुलभ बना रहा है।

इस संबंध में एक प्रमुख पहल भारत की 18,000 से अधिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) वाली साझा कंप्यूटिंग सुविधा है। 100 रुपये प्रति घंटे से कम की रियायती लागत पर उपलब्ध यह पहल सुनिश्चित करेगी कि अत्याधुनिक शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स, शिक्षाविद एवं अन्य हितधारकों के समक्ष कोई असुविधा न हो। यह पहल एआई-आधारित सिस्टम विकसित करने के लिए जीपीयू तक आसान पहुंच को सक्षम करेगी, जिसमें मूलभूत मॉडल एवं अनुप्रयोग शामिल हैं।

> भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई), एआई, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पर विशेष ध्यान देते हुए अपने डिजिटल भविष्य को आकार दे रहा है। दशकों से भारत सॉफ्टवेयर में वैश्विक नेतृत्वकर्ता रहा है, लेकिन अब हम हार्डवेयर विनिर्माण में भी बड़ी प्रगति कर रहे हैं

भारत उच्च गुणवत्ता वाले डेटा पर आधारित एआई मॉडल भी विकसित कर रहा है। यह पहल सटीकता से जानकारी उपलब्ध करवाने में मदद करेगी, जिससे एआई सिस्टम अधिक विश्वसनीय और समावेशी बनेंगे। ये डेटासेट कृषि, मौसम पूर्वानुमान और यातायात प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में एआई-संचालित समाधानों को शक्ति प्रदान करेंगे।

भारत सरकार स्वदेशी आधारभूत मॉडल के विकास में मदद कर रही है, जिसमें भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप बड़े भाषा मॉडल (एलएलएम) और समस्या-विशिष्ट एआई समाधान शामिल हैं। एआई अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं।

भारत का डीपीआई

डीपीआई के लिए भारत के प्रयासों ने वैश्विक डिजिटल परिदृश्य को महत्वपूर्ण आकार दिया है। कॉर्पोरेट या राज्य-नियंत्रित मॉडल के विपरीत भारत का मॉडल सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर आधारित है और इस पैसे का उपयोग कर आधार, यूपीआई एवं डिजीलॉकर जैसे प्लेटफ़ॉर्म को तैयार किया गया है। अब इन प्रयासों का उपयोग करते हुए निजी क्षेत्र की कंपनिया अगले चरण में डीपीआई उपयोगकर्ता के अनुकूल एप्लिकेशन-विशिष्ट समाधान तैयार कर सकती हैं और नवाचार को बढ़ावा दे सकती हैं।

इस मॉडल को अब एआई के साथ लागू किया जा रहा है भारत के डीपीआई ढांचे

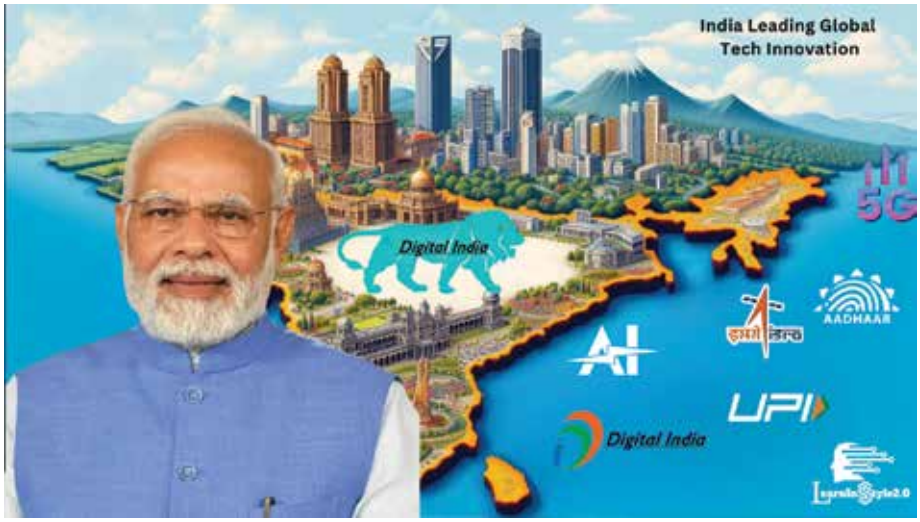

में वैश्विक रुचि जी-20 शिखर सम्मेलन में स्पष्ट थी, जहां विभिन्न देशों ने इस मॉडल को अपनाने की इच्छा व्यक्त की थी। जापान ने भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली को पेटेंट प्रदान किया है, जो इसकी कामयाबी का प्रमाण है।

महाकुंभ, परंपरा और तकनीक का संगम

भारत ने महाकुंभ 2025 के निर्बाध संचालन के लिए अपने डीपीआई और एआई संचालित प्रबंधन का लाभ उठाया, जो अब तक का सबसे बड़ा मानव समागम है। एआई संचालित उपकरणों ने प्रयागराज में रेलवे स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण करने में अहम भूमिका निभाई और रेलवे यात्रियों की आवाजाही को सुलभ बनाया।

कुंभ सहायक चैटबॉट में एकीकृत बहुभाषा प्रणाली ने आवाज आधारित खोई-पाई सुविधा उपलब्ध करवायी एवं वास्तविक समय में अनुवाद कर इसे सर्वसुलभ बनाया। भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसके सहयोग से त्वरित समस्या समाधान प्राप्त किये और एक बेहतर संचार सुविधा के माध्यम से व्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया।

डीपीआई का लाभ उठाकर महाकुंभ ने तकनीक-सक्षम प्रबंधन के लिए एक वैश्विक बेंचमार्क स्थापित किया है, जिससे यह अधिक समावेशी, कुशल और सुरक्षित बन गया है।

भविष्य के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण

भारत का कार्यबल डिजिटल क्रांति के केंद्र में है। देश हर सप्ताह एक वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) तैयार कर रहा है, जिससे हम वैश्विक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी विकास के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं।

हालांकि, इस वृद्धि को बनाए रखने के लिए शिक्षा और कौशल विकास में निरंतर निवेश की आवश्यकता होगी।

सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुसार एआई, 5जी और सेमीकंडक्टर डिजाइन को शामिल करने के लिए विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में सुधार करके इस चुनौती का समाधान कर रही है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि स्नातक स्तर पर नौकरी पाने वाला कार्यबल कौशल सक्षम होगा, जिससे शिक्षा और रोजगार के बीच का अंतर कम होगा।

भारत का कार्यबल डिजिटल क्रांति के केंद्र में है। देश हर सप्ताह एक वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) तैयार कर रहा है, जिससे हम वैश्विक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी विकास के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं

एआई को विनियमित करने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण

भारत भविष्य के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण कर रहा है, इसलिए इसके एआई विनियामक ढांचे को मजबूती से तैयार करते हुए नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। एक 'भारी-भरकम विनियामक ढांचा' — जिसमें नवाचार को दबाए जाने का जोखिम हो सकता है, या 'बाजार संचालित ढांचा', जो अक्सर कुछ लोगों के हाथों में शक्ति केंद्रित करता है, इसके विपरित भारत एक व्यावहारिक, तकनीकी-कानूनी दृष्टिकोण का पालन कर रहा है।

एआई से जुड़े जोखिमों से निपटने के लिए सिर्फ़ कानून पर निर्भर रहने के बजाय, सरकार तकनीकी सुरक्षा उपायों में निवेश कर रही है। सरकार डीपफेक, गोपनीयता संबंधी चिंताओं और साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए उपकरण विकसित करने के लिए शीर्ष विश्वविद्यालयों और आईआईटी में एआई-संचालित परियोजनाओं को वित्तपोषित कर रही है।

चूंकि एआई एक वैश्विक उद्योगों को नया आकार दे रहा है, इसलिए इसको लेकर भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट है। समावेशी विकास के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना और साथ ही नवाचार को बढ़ावा देने वाले नियामक ढांचे को तैयार करना। लेकिन नीतियों और बुनियादी ढांचे से परे, यह परिवर्तन हमारे नागरिकों के लिए है। ■

(लेखक केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, रेलवे तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं)

महिला विकास से महिला-नेतृत्व वाले विकास तक

अन्नपूर्णा देवी

जैसा कि विश्व अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है, मैं इस बात को आपके समक्ष रखना चाहती हूं कि कैसे भारत महिलाओं के विकास के युग से आगे बढ़कर अब महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की नई सुबह की ओर एक प्रेरक यात्रा पर निकल गया है। यह परिवर्तन एक महत्वपूर्ण कदम है: जो महिला केंद्रित विकास पहलों के माध्यम से महिलाओं के लिए अवसर, सेवाओं तक पहुंच और समानता सुनिश्चित करता है।

हालांकि, महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास समावेशन से कहीं आगे जाता है। यह महिलाओं को नेतृत्व की बागडोर संभालने, नवाचार को आगे बढ़ाने और नीतियों को आकार देने में सशक्त बनाता है।

महिला सशक्तीकरण को लेकर हमारे व्यवहार में एक बड़ा बदलाव आया है। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि महिलाएं विकास के केंद्र में हैं। अब सत्ता का नजरिया बदल रहा है, ताकि वे खुद बदलाव की राह तय कर सकें। महिलाएं नीतियों और कार्यक्रमों की सिर्फ निष्क्रिय लाभार्थी नहीं हैं, बल्कि अब सक्रिय बदलाव लाने वाली हैं। भारत एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जहां महिलाएं निर्णय लेने, नेतृत्व करने और नीतियों को लागू करने, व्यवसायों और सामुदायिक पहलों का नेतृत्व करने के केंद्र में हों। वे राष्ट्र को सशक्त बनाती हो। जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कहते हैं: "जब महिलाएं समृद्ध होती हैं, तो दुनिया समृद्ध होती है।" महिलाओं की यह प्रगति हमारे राष्ट्र के सशक्तीकरण को ताकत देती है।

> **महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास समावेशन से कहीं आगे जाता है। यह महिलाओं को नेतृत्व की बागडोर संभालने, नवाचार को आगे बढ़ाने और नीतियों को आकार देने में सशक्त बनाता है**

भारत ने हमेशा महिला नेतृत्व की अपनी समृद्ध परंपराओं को संजोया है और उसे कायम रखा है, जो इसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में गहराई से समाहित है। वैदिक काल में गार्गी और मैत्रेयी नेतृत्वकर्ता थीं, जिन्होंने अन्य दार्शनिकों के साथ बहस में बराबरी से भाग लिया और उस समय भी महिलाओं के लिए उपलब्ध शैक्षिक अवसरों के प्रतीक के रूप में काम किया। रानी लक्ष्मीबाई और कित्तूर रानी चेन्नम्मा जैसी महिलाएं भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की क्षेत्रीय और लैंगिक विविधता का प्रतीक थीं। आज, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी समुदाय से संबंधित पहली महिला और सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाली दूसरी महिला होने का गौरव प्राप्त है। चंद्रयान और मंगलयान मिशन काफी हद तक भारत की शानदार महिला वैज्ञानिकों की वजह से सफल हुए। उन्होंने इन पदों का नेतृत्व किया क्योंकि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) पाठ्यक्रमों में भारत के 43 प्रतिशत स्नातक महिलाएं हैं। दुनिया भर में STEM स्नातकों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 30 प्रतिशत है। आज, महिलाएं व्यवसाय, चिकित्सा और सशस्त्र बलों जैसे क्षेत्रों में अग्रणी हैं, लेकिन बदलाव सिर्फ इन्हीं तक सीमित नहीं है।

भारत भर में जमीनी स्तर पर लाखों महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में लगभग 11.5 मिलियन लखपति दीदी हैं, जो स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की सदस्य हैं और जिनकी वार्षिक घरेलू आय 1 लाख रुपये से अधिक है। ड्रोन दीदी योजना का लक्ष्य 2024-25 और 2025-2026 के बीच 15,000 चयनित एसएचजी को ड्रोन प्रदान करना है। ड्रोन का उपयोग कृषि क्षेत्रों में तरल उर्वरकों और कीटनाशकों को डालने, जल संसाधनों के प्रबंधन और पानी की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करके सिंचाई करने और मिट्टी की गुणवत्ता और उर्वरता का विश्लेषण करने के लिए

शेष पृष्ठ 28 पर...

शुचिता, सुशासन व समर्पण के संगम थे अटल बिहारी वाजपेयी

तरुण चुग

व्यक्तिगत जीवन में ईमानदारी, व्यवहार में शालीनता, स्वभाव में सादगी, सियासत में शुचिता, सरकार में सुशासन और देश के लिए समर्पण के संगम थे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी। हम सौभाग्यशाली हैं कि विराट व्यक्तित्व, करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणास्रोत, संवेदनशील साहित्यकार, महान राष्ट्रभक्त और अजातशत्रु अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मशताब्दी वर्ष मना रहे हैं। उनके विचारों का प्रभाव देश के हर नागरिक के जीवन में गहराई तक समाया हुआ है। एक यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए जो योगदान दिया, वह 21वीं सदी के भारत को राह दिखा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी उसी मार्ग पर चलते हुए एक समर्थ और समृद्ध भारत का निर्माण कर रहे हैं।

अटल जी का कृतित्व और विशाल व्यक्तित्व हमेशा राष्ट्र के बीच अमर रहेगा। वे सही मायने में भारत के रत्न थे। उन्होंने जमीन से जुड़कर राजनीति की और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। आज उनके विचार और देश के विकास की उनकी संकल्पना को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी लगातार आगे बढ़ा रहे हैं।

भारतीय राजनीति में मूल्यों और आदर्शों की पुनर्स्थापना करने वाले नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक दूरद्रष्टा विकासवादी कहा जाता है। चाहे समर्थकों में समर्पण का भाव पैदा करना हो या विरोधियों का दिल जीतना, वे दोनों में अद्वितीय थे। उनका सार्वजनिक जीवन संयमित, संस्कारित और स्वच्छ था। यही कारण था कि उनके विरोधी भी उनके प्रशंसक थे। राष्ट्रहित उनके लिए सदा सर्वोपरि रहा। जब वे संसद में बोलते थे, तो उनके विरोधी भी उनकी तर्कपूर्ण वाणी के आगे मौन रह जाते थे।

एक कवि के रूप में उन्होंने अपनी कविताओं से सामाजिक बुराइयों पर प्रहार किया और नई पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति का जज़्बा भरा।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक का सफर तय करने वाले इस युगपुरुष का जन्म 25 दिसंबर, 1924 को ग्वालियर में हुआ। उन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज (वर्तमान में लक्ष्मीबाई कॉलेज) से स्नातक किया और कानपुर के डीएवी महाविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। प्रखर वक्ता और कवि होने के गुण उन्हें अपने पिता से मिले।

छात्र जीवन में ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने और बाद में पत्रकार के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने लंबे समय तक 'राष्ट्रधर्म', 'पांचजन्य', 'स्वदेश' और 'वीर अर्जुन' जैसी राष्ट्रवादी पत्र-पत्रिकाओं का सफल संपादन किया।

अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने लंबे समय तक डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे राष्ट्रवादी नेताओं के साथ काम किया। अपनी संगठनात्मक कुशलता, बौद्धिक क्षमता और वाक्पटुता के कारण उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। 1968 से 1973 तक वे जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे।

1957 में उत्तर प्रदेश के बलरामपुर

लोकसभा सीट से पहली बार जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में विजयी होकर वे संसद पहुंचे। 1957 से 1977 तक वे जनसंघ संसदीय दल के नेता रहे। उनके ओजस्वी भाषणों से प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी प्रभावित हुए थे।

अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व सर्वसमावेशी और मिलनसार था। 1975 में उन्होंने आपातकाल का खुलकर विरोध किया। 1977 में जब देश में पहली बार गैर-कांग्रेसी सरकार बनी, तो वे मोरारजी देसाई सरकार में विदेश मंत्री बने। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय बनने का गौरव प्राप्त किया।

1980 में जनता पार्टी के टूटने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की और इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने।

1996 में भाजपा लोकसभा में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और अटल जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन यह सरकार 13

दिन ही चल सकी। इसके बावजूद वे पार्टी को मजबूत करने में जुटे रहे। 1998 में भाजपा फिर सबसे बड़ी पार्टी बनी और अटल बिहारी वाजपेयी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। यह सरकार 13 महीने तक चली।

इस छोटे कार्यकाल में ही उन्होंने परमाणु परीक्षण कर भारत की ताकत का एहसास पूरी दुनिया को कराया। अमेरिका और यूरोपीय संघ समेत कई देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन अटल जी ने इन चुनौतियों का डटकर सामना किया।

कारगिल युद्ध में भारत की जीत के बाद हुए 1999 के लोकसभा चुनाव में भाजपा फिर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के तहत 13 दलों को एकजुट कर सरकार बनाई। उनकी सरकार ने पहली बार भाजपा को पूर्ण कार्यकाल तक सत्ता में बनाए रखा। इस कार्यकाल में देश ने अभूतपूर्व प्रगति देखी।

अटल जी ने देश के चारों कोनों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत की, जिससे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को राजमार्गों से जोड़ा गया। उनके नेतृत्व में देश ने आर्थिक सुधारों की नई ऊंचाइयों को छुआ।

अटल जी को देश-विदेश में अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 2015 में भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया।

उनकी जन्मशती वर्ष पर उनकी प्रेरणादायक पंक्तियां याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं—

देखो हम बढ़ते ही जाते

उज्ज्वलतर उज्ज्वलतम होती है
महासंगठन की ज्वाला,
प्रतिपल बढ़ती ही जाती है
चंडी के मुंडों की माला॥
यह नागपुर से लगी आग
ज्योतित भारत मां का सुहाग,
उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम
दिशि दिशि गूंजा संगठन राग॥
केशव के जीवन का पराग
अंतस्थल की अवरुद्ध आग,
भगवा ध्वज का संदेश त्याग
वन विजन कान्त नगरी शान्त
पंजाब सिंधु संयुक्त प्रांत॥
केरल कर्नाटक औ' बिहार
कर पार चला संगठन राग
हिन्दू हिन्दू मिलते जाते
देखो हम बढ़ते ही जाते॥

(लेखक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं)

पृष्ठ 26 का शेष...

किया जा सकता है। पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत के बाद से इस योजना के तहत महिलाओं को 69 प्रतिशत से अधिक ऋण प्रदान किये गये हैं। भारत में लगभग 80 प्रतिशत महिलाओं के पास बैंक खाता है, जिसका संचालन वे स्वयं करती हैं। स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) और जल जीवन मिशन जैसे कार्यक्रमों ने क्रमशः शौचालय और नल के पानी तक पहुंच प्रदान करते हुए लगभग 100 मिलियन और 122 मिलियन परिवारों को लाभान्वित किया है और इस तरह लाखों महिलाओं को सशक्त बनाया है। ग्रामीण आवास कार्यक्रम के तहत पंजीकृत घरों में से 74 प्रतिशत या तो पूरी तरह से या संयुक्त रूप से महिलाओं के नाम पर हैं। मुफ्त गैस सिलेंडर वितरित करने के सरकार के कार्यक्रम ने 103 मिलियन महिलाओं के धुएं से मुक्त रसोई के सपने को साकार किया है। मई, 2024 तक 1.4 मिलियन से अधिक महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की सदस्य चुनी गईं, जिसमें सरपंच का पद भी शामिल है। यह पीआरआई के कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का 46 प्रतिशत है। महिला सरपंच अपने गांवों में पानी, सौर ऊर्जा, पक्की सड़कें, शौचालय और बैंकों को बेहतर बनाने की परियोजनाओं में शामिल रही हैं।

महिलाओं को आवाज उठाने और नेतृत्व करने में सक्षम बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता है। हमारी सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक जैसे ऐतिहासिक कानूनों के माध्यम से इस एजेंडे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण की गारंटी देता है। मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन कर महिलाओं को 26 सप्ताह तक के सवेतन मातृत्व अवकाश की गारंटी भी दी गयी। महिला हेल्पलाइन और शी-बॉक्स जैसी पहल संकट में महिलाओं को सहायता प्रदान करती हैं, जबकि 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) योजना' का लक्ष्य देश भर में 1,000 कामकाजी महिला छात्रावास स्थापित करना है, जिससे आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा।

भारत की जी-20 अध्यक्षता के दौरान महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान का समर्थन ब्राजील ने भी किया, जिसने 2024 में जी-20 की अध्यक्षता की। यह महिलाओं की पूरी क्षमता का उपयोग करने, उनके अमूल्य योगदान को मान्यता देने और प्रगति एवं समृद्धि की यात्रा में एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उनकी भूमिका को स्वीकार करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आइए, हम सब मिलकर #AccelerateAction के लिए एकजुट हों और भारत के भविष्य को आकार देने की जिम्मेदारी लें। हम सभी को हाथ मिलाना चाहिए, बदलाव को अपनाना चाहिए और प्रगति एवं सशक्तीकरण की दिशा में इस प्रेरक यात्रा का हिस्सा बनना चाहिए।

(लेखक केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं)

नारी सशक्तीकरण हमारी प्राथमिकता

भजनलाल शर्मा

भारत में प्राचीन काल से ही महिलाओं के सम्मान की परम्परा और संस्कृति रही है। भारतीय परम्परा एवं इतिहास में इससे संबंधित उदाहरणों की कमी नहीं है। नारी और शक्ति शब्दों को एक-दूसरे का पर्याय कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जब नारी के साथ शक्ति शब्द जुड़ जाता है तो वह 'मां दुर्गा' का साक्षात् अवतार ही बन जाती है और उसमें घर, समाज तथा दुनिया में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध लड़ने की एक अदम्य शक्ति उत्पन्न हो जाती है। सामाजिक एवं आर्थिक बुराई की अन्दरूनी सच्चाई के साथ-साथ समाज की घरेलू समस्याओं, महिलाओं से जुड़े मामलों, पुलिस प्रताड़ना, नशा, कैशौर्य समस्याओं और अपराध आदि का हमें गंभीरता से विश्लेषण करना चाहिए। उनकी कहानियां समाज में व्याप्त उन असामाजिक लोगों को भी सावधान करती हैं, जो नारी शक्ति शोषण करते हैं, और उसे प्रश्रय देते हैं। आज आधी आबादी की आवाज का दम नहीं घोटा जा सकता है। हर नारी शांति की किरण है, जो बुराइयों के अंधेरे को अपनी अदम्य नारीत्व शक्ति से दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। नारी के सम्मान को पुनर्स्थापित करने की आज महती आवश्यकता है। वैदिक काल में महिलाओं ने ऋचाओं की रचना की। वह विद्वतापूर्ण शास्त्रार्थ में सहभागी होती थीं। युद्ध क्षेत्र में उनकी भूमिका वीरांगनाओं के रूप में रहती थी। विदेशी आक्रान्ताओं के समय में महिलाओं की उपेक्षा शुरू हुई थी, इस कारण हमारे समाज में अनेक कमजोरियों ने स्थान बना लिया। रत्नप्रसूता भारत भूमि रानी अहिल्या बाई, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती जैसी अनेक वीरांगनाओं की जन्म एवं कर्मभूमि रही है।

वर्तमान में हमारी सरकार ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे अभियान का शुभारंभ किया जो सार्थक रूप में निरन्तर आगे बढ़ा है। इससे बेटियों के प्रति सम्मान, उनकी स्वास्थ्य शिक्षा, सुरक्षा के विषय शामिल हैं। इसके साथ ही महिला स्वावलंबन पर भी जोर दिया जा रहा है। आधी आबादी को उपेक्षित कर कोई देश विकास नहीं कर सकता। किसी भी सभ्य समाज में राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए या किसी से प्रतिशोध लेने के लिए महिलाओं-बच्चों पर जुल्म ढाना एक अक्षम्य अपराध होता है। उसे झेलने वाले समाज में क्रोध एवं हताशा का मिला-जुला भाव पैदा करता है।

देश और प्रदेशों में जहां-जहां भाजपा सरकारें हैं, वहां नारी सशक्तीकरण हमारी प्राथमिकताओं में है। हमारी सरकारें महिलाओं को रोजगार के समान अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 40 करोड़ जन-धन खातों में 22 करोड़ खाते महिलाओं के हैं। 35 करोड़ के करीब मुद्रा लोन दिए गए हैं। 70 फीसदी मुद्रा लोन लेने वाली महिलाएं हैं। यही नहीं, आज भारत दुनिया के उन देशों में है, जहां नौ-सेना और वायु सेना में महिलाओं को कोम्बेट रोल में शामिल किया जा रहा है।

> **नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन एक साथ जुड़ेंगे, तो नारी सशक्तीकरण का लक्ष्य स्वतः ही पूरा होगा**

कन्या भ्रूण हत्या हमारे लिए एक अभिशाप है। गर्भ में बेटी का पता लगते ही गर्भपात करा देने से सामाजिक संतुलन बिगड़ रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी ने इस असंतुलन को समाप्त करने के लिए 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान चलाया।

सुकन्या समृद्धि योजना में बेटियों की शिक्षा से लेकर विवाह तक की व्यवस्था की गई है। महिला कामगारों के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि में वृद्धि की गई है। यह अवधि बढ़ाकर 26 सप्ताह (6 माह) कर दी गई है ताकि वे अपने नवजात शिशु की अच्छी तरह देखभाल कर सकें। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत 42 प्रतिशत नामांकन महिलाओं के हैं। अटल पेंशन योजना बैंक एवं डाकघरों के माध्यम से सदस्यता के लिए खुली है। अभी हाल ही में विधानसभा में प्रस्तुत बजट में 3 लाख महिलाओं को 'लखपति दीदी योजना' के अन्तर्गत 1.5 प्रतिशत ब्याज दर से लोन उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर मुख्यमंत्री सुपोषण-किट योजना तथा बालिका गृह में 50 बेड की सरस्वती होम बनाए जाने की घोषणा हमारी सरकार ने की है। 10 जिला मुख्यालयों पर गर्ल-चाइल्ड केयर सेंटर की स्थापना के साथ ही आंगनबाड़ी में सप्ताह में 5 दिन दुग्ध-वितरण की घोषणा की गई है। 10 लाख नए परिवार खाद्य-सुरक्षा योजना में शामिल करने की घोषणा भी प्रदेश के 2025-26 के बजट में की गई है।

देश की महिलाओं के कल्याण के लिए पं. दीनदयाल अन्त्योदय योजना के जरिये भी बहनों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जा रहा है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है। मुस्लिम बहनों को उत्पीड़न एवं शोषण से बचाने के लिए तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाया गया है। कुछ वर्षों पहले तक बेसिक स्कूलों में शौचालय न होने के कारण बालिकाएं आगे की पढ़ाई छोड़ने को विवश हो जाती थीं। सरकार ने इस समस्या का समाधान भी किया, जिससे वे गौरवपूर्ण जीवन जीएं।

नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन एक साथ जुड़ेंगे, तो नारी सशक्तीकरण का लक्ष्य स्वतः ही पूरा होगा। ■

(लेखक राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं)

'असम' भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 फरवरी को असम के गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 निवेश एवं अवसंरचना शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत आज भविष्य की एक नई यात्रा पर निकल रहे हैं और एडवांटेज असम, असम की अविश्वसनीय क्षमता और प्रगति को दुनिया के साथ जोड़ने की एक बड़ी पहल है। उन्होंने कहा कि इतिहास भारत की समृद्धि में पूर्वी भारत की प्रमुख भूमिका का साक्षी है।

प्रधानमंत्री ने आशा जताते हुए कहा कि आज जब हम 'विकसित भारत' की ओर बढ़ रहे हैं तो इस दिशा में पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर अपनी वास्तविक क्षमता प्रदर्शित करेंगे। उन्होंने कहा कि एडवांटेज असम उसी भावना का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री ने इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन के लिए असम सरकार और मुख्यमंत्री को बधाई दी। उन्होंने 2013 के अपने शब्दों का भी स्मरण किया, जब उन्होंने कहा था कि वह समय दूर नहीं जब 'ए फॉर असम' आदर्श बन जाएगा।

आज पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत बुनियादी ढांचे, रसद, कृषि, पर्यटन और उद्योग में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वह दिन दूर नहीं, जब दुनिया इस क्षेत्र को भारत की विकास यात्रा का नेतृत्व करते हुए देखेगी

असम की अर्थव्यवस्था केवल छह वर्षों में दोगुनी हो गई

असम में उपस्थित जनसमूह द्वारा भारत में बढ़ते वैश्विक विश्वास की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत के विकास में असम का योगदान निरंतर रूप से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि एडवांटेज असम शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण 2018 में आयोजित किया गया था, उस समय असम की अर्थव्यवस्था का मूल्य 2.75 लाख करोड़ रुपये था। आज, असम लगभग 6 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन चुका है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के नेतृत्व में असम की अर्थव्यवस्था केवल छह वर्षों में दोगुनी हो गई है। श्री मोदी ने कहा कि यह केंद्र और राज्य में उनकी सरकारों का दोहरा प्रभाव है। उन्होंने कहा कि असम में कई निवेशों ने इसे असीमित संभावनाओं वाले राज्य में बदल दिया है।

श्री मोदी ने कहा कि 2014 से पहले ब्रह्मपुत्र नदी पर केवल तीन सेतु थे, जिनका निर्माण 70 वर्षों में बनाया गया था। हालांकि, पिछले 10 वर्षों में चार नए सेतुओं का निर्माण किया गया है। इनमें से एक सेतु का नाम 'भारत रत्न' भूपेन हजारिका के नाम पर रखा गया है। श्री मोदी ने कहा कि 2009 से 2014 के बीच असम को औसतन 2,100 करोड़ रुपये का रेल बजट मिला था, लेकिन उनकी सरकार ने असम के रेल बजट को चार गुना से अधिक बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये कर दिया। असम में हवाई संपर्क के तेजी से विस्तार का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 तक केवल सात मार्गों पर उड़ानें संचालित होती थीं, लेकिन अब लगभग 30 मार्गों पर उड़ानें हैं।

वैश्विक व्यापार में हमेशा से असम की हिस्सेदारी का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के तटीय प्राकृतिक गैस उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक असम से आता है और हाल के वर्षों में असम की रिफाइनरियों की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि असम इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में तेजी से उभर रहा है।

प्रधानमंत्री ने गर्व से कहा कि असम भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है और हाल ही में असम के जगीरोड में टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा के उद्घाटन का उल्लेख किया, जो पूर्वोत्तर में तकनीकी विकास को बढ़ावा देगा।

पूर्वी भारत के 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत बुनियादी ढांचे, रसद, कृषि, पर्यटन और उद्योग में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वह दिन दूर नहीं, जब दुनिया इस क्षेत्र को भारत की विकास यात्रा का नेतृत्व करते हुए देखेगी। ■

मध्य प्रदेश कृषि एवं खनिज के मामले में भारत के शीर्ष राज्यों में से एक है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 फरवरी को मध्य प्रदेश के भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कार्यक्रम में देरी के लिए माफ़ी मांगी, क्योंकि 10वीं और 12वीं के छात्रों की बोर्ड परीक्षाएं चल रही थीं और कार्यक्रम में जाने के दौरान उनके सुरक्षा संबंधी उपायों के कारण छात्रों को असुविधा हो सकती थी। श्री मोदी ने कहा कि राजा भोज की धरती पर निवेशकों और व्यापार जगत के दिग्गजों का स्वागत करना उनके लिए बहुत गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि आज का कार्यक्रम महत्वपूर्ण था, क्योंकि 'विकसित भारत' की यात्रा में 'विकसित मध्य प्रदेश' की आवश्यकता है।

दो दशक पहले लोग मध्य प्रदेश में निवेश करने से हिचकिचाते थे, जबकि आज मध्य प्रदेश निवेश के लिए देश के शीर्ष राज्यों में से एक बन गया है

श्री मोदी ने कहा, "पूरी दुनिया भारत को लेकर आशावादी है।" उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा अवसर पहली बार आया है। उन्होंने कहा कि आम नागरिक हों या नीति विशेषज्ञ या संस्थाएं या दुनिया के देश, सभी को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले कुछ हफ्तों में भारत के बारे में जो टिप्पणियां मिली हैं, उनसे निवेशकों का उत्साहवर्धन होगा। विश्व बैंक द्वारा हाल ही में दिए गए उस बयान को याद करते हुए कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा, प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ओईसीडी के एक प्रतिनिधि ने टिप्पणी में कहा, "दुनिया का भविष्य भारत में है।"

यह बताते हुए कि मध्य प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से भारत का पांचवां सबसे बड़ा राज्य है, श्री मोदी ने कहा, "मध्य प्रदेश कृषि और खनिज के मामले में भारत के शीर्ष राज्यों में से एक है।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मध्य प्रदेश को जीवनदायिनी नर्मदा नदी का आशीर्वाद प्राप्त है। उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में सकल घरेलू उत्पाद के हिसाब से भारत के शीर्ष पांच राज्यों में से एक बनने की क्षमता है।

श्री मोदी ने कहा कि दो दशक पहले लोग मध्य प्रदेश में निवेश करने से हिचकिचाते थे, जबकि आज मध्य प्रदेश निवेश के लिए देश के शीर्ष राज्यों में से एक बन गया है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्य, जो कभी खराब सड़कों से जूझ रहा था, अब भारत की ईवी क्रांति में अग्रणी राज्यों में से एक है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि जनवरी 2025 तक मध्य प्रदेश में लगभग 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत किए गए थे, जो लगभग 90 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है, जो इस बात का संकेत है कि मध्य प्रदेश नए विनिर्माण क्षेत्रों के लिए एक उत्कृष्ट गंतव्य बन रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा, "भारत ने पिछले एक दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उछाल देखा है।" उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश को इस विकास से बहुत लाभ हुआ है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, जो दो प्रमुख शहरों को जोड़ता है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है, जो मुंबई के बंदरगाहों और उत्तर भारत के बाजारों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करता है। उन्होंने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश में अब पांच लाख किलोमीटर से ज्यादा का सड़क नेटवर्क है।

पिछले 10 वर्षों में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 70 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश

श्री मोदी ने कहा, "पिछले दशक में भारत के ऊर्जा क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।" उन्होंने कहा कि भारत ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जो कभी अकल्पनीय थी। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 70 बिलियन डॉलर (5 ट्रिलियन रुपये से अधिक) से अधिक का निवेश किया गया है और इस निवेश ने पिछले साल अकेले स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में 10 लाख से अधिक रोजगार का सृजन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में इस उछाल से मध्य प्रदेश को बहुत लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि आज मध्य प्रदेश लगभग 31,000 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता के साथ बिजली की मांग से अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, जिसमें से 30 प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा है।

यह बताते हुए कि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बनने के बाद विकास की गति दोगुनी हो गई है, श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार राज्य और देश के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। ■

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

भारत के असंगठित कार्यबल के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना

"पीएम-एसवाईएम असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों को बुढ़ापे में मासिक पेंशन सुनिश्चित करेगा। आजादी के बाद पहली बार अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों श्रमिकों के लिए ऐसी योजना की परिकल्पना की गई है।" —प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम), केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। यह योजना असंगठित क्षेत्र से संबंधित उन श्रमिकों के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन सुनिश्चित करती है, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये तक है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सम्मान है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 50 प्रतिशत का योगदान करते हैं।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों में ज़्यादातर घर में काम करने वाले मजदूर, रेहड़ी-पटरी वाले, मिड-डे मील वर्कर, सिर पर बोझा ढोने वाले, ईंट भट्ठा मजदूर, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, कृषि मजदूर, निर्माण स्थल पर काम करने वाले मजदूर, बीड़ी मजदूर, हथकरघा मजदूर, चमड़ा मजदूर, ऑडियो-विजुअल मजदूर या इसी तरह के दूसरे कामों में लगे हुए कामगार शामिल हैं। ई-श्रम पोर्टल के अनुसार 31 दिसंबर, 2024 तक 30.51 करोड़ से ज़्यादा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर पंजीकृत हैं।

पीएम-एसवाईएम को अंतरिम बजट 2019 में पेश किया गया था। यह योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और कॉमन सर्विस सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीएससी एसपीवी) के सहयोग से निर्बाध कार्यान्वयन के लिए प्रशासित की जाती है। एलआईसी पेंशन फंड मैनेजर है और पेंशन भुगतान के लिए उत्तरदायी है। यह योजना सरकार की व्यापक सामाजिक सुरक्षा पहलों का एक हिस्सा है और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक पेंशन कवरेज के विजन के अनुरूप है।

पीएम-एसवाईएम की मुख्य विशेषताएं

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अनेक लाभ प्रदान करती है।

- **न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन :** 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रति माह।
- **सरकारी अंशदान :** केंद्र सरकार 1:1 के आधार पर श्रमिक के अंशदान के बराबर अंशदान करती है।
- **स्वैच्छिक और अंशदायी :** यह योजना स्वैच्छिक है, जो श्रमिकों को उनकी सामर्थ्य और आवश्यकता के आधार पर अंशदान करने की अनुमति देती है।
- **पारिवारिक पेंशन :** यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो पति/पत्नी को पेंशन राशि का 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलता है। पारिवारिक पेंशन केवल पति/पत्नी को ही मिलती है।
- **निकास प्रावधान :** प्रतिभागी निर्दिष्ट शर्तों (धारा 9 में विस्तृत रूप में है) के अधीन योजना से बाहर निकल सकते हैं।
- **आसान पंजीकरण :** पात्र श्रमिक सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) या मानधन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं।
- **निधि प्रबंधन :** यह योजना एलआईसी द्वारा प्रशासित है, जो वित्तीय स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है।

पात्रता मानदंड

पीएम-एसवाईएम में पंजीकरण के लिए व्यक्तियों को निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:

- **आयु आवश्यकता :** 18 से 40 वर्ष।
- **आय सीमा :** मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
- **असंगठित क्षेत्र रोजगार :** निम्नलिखित व्यवसायों में लगे श्रमिकः रेहड़ी-पटरी वाले, कूड़ा बीनने वाले, रिक्शा चालक; निर्माण स्थल पर काम करने वाले श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर; कृषि श्रमिक, बीड़ी श्रमिक; घरेलू कामगार, बुनकर, कारीगर, मछुआरे, चमड़ा कामगार आदि।
- **एक्सक्लूजन मानदंड :**

क. कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), या राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए।

ख. आयकरदाता नहीं होना चाहिए।

ग. किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रहा हो।

- **आवश्यक दस्तावेज़ :** आधार कार्ड; IFSC सहित बचत बैंक खाता या जन धन खाता विवरण; मोबाइल नंबर।

योगदान संरचना

पंजीकरण के समय उम्र के आधार पर अंशदान की राशि अलग-अलग होती है। जितनी जल्दी कोई कर्मचारी पंजीकरण करवाता है, मासिक अंशदान उतना ही कम होता है।

प्रवेश के समय आयु	मासिक अंशदान (कर्मचारी द्वारा)	सरकार द्वारा समान अंशदान
18 वर्ष	55 रुपए	55 रुपए
20 वर्ष	65 रुपए	65 रुपए
25 वर्ष	80 रुपए	80 रुपए
30 वर्ष	105 रुपए	105 रुपए
35 वर्ष	150 रुपए	150 रुपए
40 वर्ष	200 रुपए	200 रुपए

60 वर्ष की आयु होने पर लाभार्थियों को जीवन भर 3,000 रुपये प्रति माह की निश्चित पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है।

पंजीकरण प्रक्रिया

पीएम-एसवाईएम में पंजीकरण की सुविधा पूरे भारत में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से उपलब्ध है। इसमें निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

- आधार और बचत बैंक खाते के साथ किसी सीएससी पर जाएं।
- आधार का उपयोग करके बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रदान करें।
- ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरें।
- प्रथम सदस्यता का भुगतान नकद करना होगा।
- बैंक खाते से ऑटो-डेबिट सुविधा चुनें।
- सफल पंजीकरण पर पीएम-एसवाईएम कार्ड प्राप्त करें।
- वैकल्पिक रूप से पात्र श्रमिक मानधन पोर्टल (https://maandhan.in/) के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं।

राज्य और केंद्र सरकारों के सभी श्रम कार्यालय, एलआईसी के सभी शाखा कार्यालय, ईएसआईसी/ईपीएफओ के कार्यालय अपने सुविधा डेस्क/सहायता डेस्क पर असंगठित श्रमिकों को योजना, इसके लाभों और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। ग्राहक सेवा नंबर 1800 2676 888 (24 घंटे उपलब्ध) और वेब पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की सुविधा है।

कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति

इस योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र के कामगारों तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठक आयोजित करना।

- राज्य सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) प्रमुखों के साथ नियमित बैठक।
- स्वैच्छिक निकास, रिवाइवल मॉड्यूल, दावा स्थिति और खाता विवरण जैसी नई सुविधाओं की शुरुआत।
- निष्क्रिय खातों के नवीनीकरण की अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष की गई।
- पीएम-एसवाईएम और ई-श्रम का दो-तरफ़ा एकीकरण।
- जागरूकता पैदा करने के लिए एसएमएस अभियान।
- पीएम-एसवाईएम योजना के अंतर्गत पंजीकरण के संबंध में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ बातचीत।
- पीएम-एसवाईएम पेंशन योजना के अंतर्गत अपने कर्मचारियों के प्रीमियम का भुगतान करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा पंजीकरण बढ़ाने के लिए डोनेट-ए-पेंशन मॉड्यूल का शुभारंभ।
- पेंशन योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए वित्तीय सेवा विभाग, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय लोक वित्त और नीतिगत संस्थान के साथ बातचीत।

निकास और वापसी प्रावधान

असंगठित श्रमिकों की कठिनाइयों और रोजगार की अनिश्चित प्रकृति को ध्यान में रखते हुए योजना के निकास प्रावधानों को लचीला रखा गया है।

- **10 वर्ष से पहले बाहर निकलना :** यदि कोई कर्मचारी 10 वर्ष से पहले योजना से बाहर निकलता है, तो योगदान की गई राशि बचत बैंक ब्याज दर के साथ वापस कर दी जाती है।
- **10 वर्ष के बाद, लेकिन 60 वर्ष की आयु होने से पहले निकासी:** लाभार्थी को उसके अंशदान का हिस्सा, निधि द्वारा अर्जित संचित ब्याज या बचत बैंक ब्याज दर, जो भी अधिक हो, के साथ प्राप्त होता है।

60 वर्ष से पहले मृत्यु या दुर्घटना के कारण स्थायी दिव्यांगता :

क. पति या पत्नी योजना को जारी रख सकते हैं या

ख. योगदान की गई राशि को फंड द्वारा वास्तव में अर्जित ब्याज या बचत बैंक ब्याज दर, जो भी अधिक हो, सहित निकाल सकते हैं।

ग. 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु : पति/पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में पेंशन का 50 प्रतिशत मिलता है।

- पंजीकृत कामगार तथा उसके जीवनसाथी की मृत्यु के बाद सम्पूर्ण धनराशि वापस निधि में जमा कर दी जाएगी।

चूक की स्थिति : यदि किसी पंजीकृत कामगार ने लगातार अंशदान का भुगतान नहीं किया है, तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित दंड शुल्क (यदि कोई हो) के साथ संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करके अपने अंशदान को नियमित करने की अनुमति दी जाएगी।

निष्कर्ष

पीएम-एसवाईएम एक ऐतिहासिक पहल है, जो लाखों असंगठित श्रमिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। 3,000 रुपये की मासिक पेंशन सुनिश्चित करके यह श्रमिकों को सेवानिवृत्ति के बाद एक सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करती है। बड़ी संख्या में पंजीकरण और चल रहे प्रचार प्रयासों के साथ पीएम-एसवाईएम का उद्देश्य सार्वभौमिक पेंशन कवरेज प्रदान करना है, जिससे भारत में एक अधिक समावेशी सामाजिक सुरक्षा ढांचा तैयार हो सके। ■

महाकुंभ में 8 लाख श्रद्धालुओं को आयुष का लाभ मिला

लाखों श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए आयुष मंत्रालय ने आठ लाख से अधिक तीर्थयात्रियों को व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कीं, जिससे महाकुंभ मेले के दौरान उनकी पवित्र यात्रा सुरक्षित और स्वस्थ रही।

केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा 27 फरवरी को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार 20 आयुष ओपीडी स्थापित करने से लेकर मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों की तैनाती तक, 90 से अधिक डॉक्टर और 150 स्वास्थ्यकर्मी पूरे भव्य आध्यात्मिक आयोजन के दौरान निरंतर चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। इन समर्पित प्रयासों ने सुनिश्चित किया कि भक्त, कल्पवासी और संत बिना किसी स्वास्थ्य संबंधी चिंता के पवित्र उत्सव में भाग ले सकें, खासकर पवित्र महाशिवरात्रि स्नान के दौरान।

मोबाइल आयुष स्वास्थ्य इकाइयों ने पूरे मेला क्षेत्र में दवाइयां वितरित कीं, जबकि विभिन्न टीमों ने विभिन्न आयुष सुविधाओं पर छतरियों से कार्य करते हुए कल्पवासियों को आवश्यक स्वास्थ्य जांच उपलब्ध कराई।

श्रद्धालुओं को आम बीमारियों से बचाने के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) ने एक विशेष पहल की शुरुआत की, जिसके तहत 10,000 आयुष रक्षा किट वितरित की गईं, जिनमें आवश्यक आयुर्वेदिक दवाएं और स्वास्थ्य उत्पाद शामिल थे। इस पहल के साथ ही एक सप्ताह तक चलने वाला स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया, जिसमें 15,000 तीर्थयात्रियों को लाभ मिला, जिससे निवारक और समग्र स्वास्थ्य सेवा के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को बल मिला।

इस आयोजन में हरित स्पर्श जोड़ते हुए राष्ट्रीय औषधीय पौध बोर्ड (एनएमपीबी) ने श्रद्धालुओं को 25,000 से अधिक औषधीय पौधे वितरित किए, जिनमें तुलसी, अश्वगंधा, शतावरी, नीम, आंवला और करी पत्ता शामिल हैं, जिससे प्राकृतिक उपचार को बढ़ावा मिला और दैनिक जीवन में औषधीय पौधों के महत्व पर बल मिला।

महाकुंभ मेला सिर्फ़ आध्यात्मिक जागृति के लिए न होकर यह उन लाखों लोगों की भलाई के लिए भी है, जो इस पवित्र यात्रा पर निकलते हैं। आयुष मंत्रालय इस भव्य आयोजन में पारंपरिक स्वास्थ्य सेवा को एकीकृत करने के अपने प्रयासों के लिए प्रतिबद्ध रहा, जिससे समग्र स्वास्थ्य आध्यात्मिक अनुभव का एक अभिन्न अंग बन गया। ■

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बनें

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

03 मार्च, 2025 को विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

गुजरात में 04 मार्च, 2025 को वनतारा वन्यजीव बचाव, पुनर्वास एवं संरक्षण केंद्र का उद्घाटन एवं भ्रमण करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नवसारी (गुजरात) में 08 मार्च, 2025 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में भाग लेते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

हरसिल (उत्तराखंड) में 06 मार्च, 2025 को 'शीतकालीन पर्यटन' को बढ़ावा देने के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में 28 फरवरी, 2025 को यूरोपीय संघ की अध्यक्ष सुश्री उर्सुला वॉन डेर लेयेन से भेंट करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

गुवाहाटी असम में 25 फरवरी, 2025 को एडवांटेज असम 2.0 निवेश एवं अवसंरचना शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश

अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध

लॉग इन करें:

www.kamalsandesh.org

राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh
@KamalSandesh
kamal.sandesh
KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित
प्रकाशन तिथि: 17 मार्च, 2025
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2025-27
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2021-23

छायाकार: अजय कुमार सिंह